विषय–सूची

jk"Vªh; turkaf=d xBca/ku ¼,uMh,½ us iz/kkuea=h MkW- eueksgu flag ls ekax dh fd og Hkz"Vkpkj ds ekeyksa dh tkap ds fy, vxj tsihlh dk xBu djus esa vleFkZ gSa rks uSfrd vk/kkj ij viuk in ls bLrhQk ns nsaA

घोटाले और भ्रष्टाचार के विरुद्ध महासंग्राम रैली

राजग नेताओं का संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस... 10
राजग की प्रधानमंत्री से मांग : जेपीसी गठित करें या पद छोड़ें... 15

विदेश प्रवास

इस्राइल में भाजपा अध्यक्ष का भव्य स्वागत.................................. 7

लेख

कांग्रेस का भ्रष्टाचार से संग्राम का ढोंग
vEckpj.k of'k"B.. 22
मध्यप्रदेश लोकसवा अधिनियम 2010 एक अनुकरणीय कदम
fodkl vkuUn.. 25

मोर्चा / प्रकोष्ठ

भाजपा दिल्ली प्रदेश विधि प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित संगोष्ठी........... 12
भाजयुमो फहराएगा श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा.................. 26

राज्यों से

eè; çns'k ½ कोयला सत्याग्रह.. 27
vkfM'kk ½ प्रदेश कार्यसमिति बैठक सम्पन्न................................. 29
vkU/kz izns'k ½ तेलंगाना राज्य गठन के लिए प्रधानमंत्री को ज्ञापन... 30

अन्य

भाजपा राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक, जम्मू में पारित प्रस्ताव............. 19
सुषमा स्वराज ने उठाये चीनी प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय मुद्दे.................. 24

कमल संदेश

ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिवशक्ति बक्सी

संपादक मंडल

सत्यपाल
संजीव कुमार सिन्हा

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/–
त्रि वार्षिक : 250/–

संपर्क

lnL;rk : +91(11) 23005798
Qksu (dk-) : +91(11) 23381428
QSDl : +91(11) 23387887

ई–मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

संपादक के नाम पत्र...

कांग्रेस का राष्ट्रघाती एजेंडा

अनेक महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन कर सारे विश्व में सनसनी फैला देने वाली वेबसाइट विकिलीक्स द्वारा कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी की देश को लश्करे तोयबा से ज्यादा हिन्दू आतंकवाद से खतरा बताए जाने की अमेरीकी राजदूत टीमोथी रोएमर से की गई बातचीत का खुलासा किए जाने से न केवल देश की राजनीति में गरमाहट आई है बल्कि इस खुलासे ने कांग्रेस की स्थापना के 125 वर्ष पूरे होने पर आयोजित हुए अधिवेशन के एजेंडे को भी बदल दिया है। राहुल गांधी के बयान से एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस सत्ता के लिए मुस्लिम वोटों की राजनीति के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। एक विदेशी व्यक्ति द्वारा स्थापित की गई कांग्रेस के 125वें वर्ष में एक विदेशी मूल की अध्यक्षा के नेतृत्व में हो रहे अधिवेशन में कांग्रेस केवल भ्रष्टाचार पर बयान देती नजर आई उससे निबटने के लिए उसके पास न इच्छा शक्ति है और न ही कोई कार्यक्रम है। इस अधिवेशन में कांग्रेस का यह ऐजेंडा भी बेनकाब हो गया है कि वह एक साजिश के तहत देश के सहिष्णु, उदारवादी हिन्दू समाज के आतंकवादी सिद्ध कर देश में आतंक फैलाने वाले संगठनों को संरक्षण दे रही है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का झूठ देश के सामने उजागर हुआ कि शहीद करकरे ने मरने से दो घंटे पूर्व उन्हें फोन कर हिन्दू आतंकवाद से जान का खतरा बताया था। कांग्रेस की महाराष्ट्र सरकार और करकरे की पत्नी ने दिग्विजय के बयान के झूठ की पोल खोल दी है। कांग्रेस संसद पर हमले के मामले में फांसी की सजा पाने वाले अफजल को माफी दिए जाने की पैरवी करती रही है। कसाब की सुरक्षा पर भी देश की गाढ़ी कमाई खर्च रही है। कांग्रेस ने हमेशा मूठभेड में आतंकियों के मारे जाने पर उन्हें फर्जी करार दिया है और राष्ट्रवादी हिन्दू संगठनों व हिन्दू नेताओं को बदनाम किया है। अब अपने अधिवेशन में शिशु मंदिरों में आतंकवाद सिखाने का बेबुनियाद आरोप लगाने वाली कांग्रेस जो स्वयं इस्लामी इसाई आतंकवाद को खुला संरक्षण देती रही है, अपने राष्ट्रघाती एजेंडे पर एकदम खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस के शासन में देश के हालात अंग्रेजी, मुगल शासन से बदतर हो गए हैं। कांग्रेस में शामिल स्वाभिमानी, राष्ट्रवादियों को चाहिए कि वे बंधुओं कार्यकर्ता के शिकंजे को तोड़कर राष्ट्रहित में कांग्रेस की राष्ट्रविरोधी मुहिम का मुखर विरोध करे। अन्यथा इतिहास में वे भी कांग्रेस के राष्ट्रघात के लिए जिम्मेदार समझे जायेंगे। कांग्रेस को भी समझ लेना चाहिए कि जिस दिन देश के लोगों का स्वाभिमान जाग गया, देश से कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

—कमल कुमार जैन
2054 गली नं. 6, कैलाश नगर, दिल्ली

हमें लिखें..

सम्पादक के नाम पत्र

कमल संदेश

सादर आमंत्रित

आपकी राय एवं विचार

सम्पादक,
कमल संदेश
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66
सुब्रहमण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
ई-मेल:
kamalsandesh@yahoo.co.in

0;X; fp=

....एक और भ्रष्टाचार विरोधी 'संपूर्ण क्रांति' की जरूरत

कांग्रेसनीत यूपीए सरकार की गलत नीतियों के चलते आज तबाही के कगार पर खड़ा है भारत। भ्रष्टाचार से पूरा देश कराह रहा है तो महंगाई से त्रस्त है जनता। लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। यह पूरी तरह से गूंगी, बहरी और असंवेदनशील हो चुकी है।

यूपीए सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेता भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं। घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। एनडीए के कार्यकारी अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने सही कहा है 2010 घोटालों का वर्ष है। आईपीएल खेल घोटाले ने केन्द्र सरकार के भ्रष्टाचार की कलई खोल दी। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में हुए भ्रष्टाचार से पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हुई। महाराष्ट्र में आदर्श सहकारी आवास घोटाले से कांग्रेस की बड़ी फजीहत हुई क्योंकि आवास सोसाइटी ने रक्षा सेनाओं में कार्यरत तथा सेवानिवृत्त कमिर्यों के कल्याण के लिए महाराष्ट्र सरकार से भूमि आवंटित किये जाने की मांग की थी। कैग की रिपोर्ट के अनुसार, 2जी स्पेक्ट्रम के आवंटन में उचित प्रक्रिया नहीं अपनाने से सरकारी खजाने को करीब एक लाख 76 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इतनी रकम से देश के हर भूखे व्यक्ति का पेट अगले दस साल तक भरा जा सकता था।

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सारा विपक्ष एकजुट हो गया है। विपक्षी राजग, वाम, अन्नाद्रमुक और सपा सदस्य 2–जी स्पेक्ट्रम आवंटन, आदर्श आवासीय सोसायटी और राष्ट्रमंडल खेल से जुड़ी परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने की मांग की है, लेकिन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जेपीसी के गठन की मांग ठुकरा दी। प्रधानमंत्री पीएसी के सामने जवाब देने के लिए तैयार हैं लेकिन जेपीसी के गठन के खिलाफ हैं। आखिर क्यों? उन्होंने जेपीसी गठन से किस बात का भय है? यदि प्रधानमंत्री में जेपीसी जांच का सामना करने का साहस नहीं है तो उन्हें तुरंत अपना पद छोड़ देना चाहिए।

राज्यों में सुशासन की लहर चल रही है, विकास की राजनीति को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। भाजपा शासित राज्यों में बेहतर तरीके से नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है और जन–कल्याणकारी योजना के माध्यम से लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि भाजपा की कार्यपद्धति में सरकार साधन है, साध्य नहीं। पार्टी का उद्देश्य है समाज परिवर्तन, वहीं कांग्रेस का उद्देश्य है येन–केन–प्रकारेण सत्ता में बने रहना। भारत वैभवशाली बने, लोग खुशहाल हों, इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है वह तो बस जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका डालना जानती है।

हाल ही में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के 83वें महाधिवेशन में सोनिया और राहुल ने दोमुंही बातें कही कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी। यह हास्यास्पद और शर्मनाक हैं। कांग्रेस अध्यक्ष की नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है और वे बयान जारी कर रही हैं। वास्तव में सोनिया–मनमोहन सरकार तानाशाह हो गई है। सन् 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकतांत्रिक मूल्यों पर कुठाराघात करते हुए देश पर तानाशाही विचारधारा आपातकाल थोप दी थी। लेकिन तब जनता ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करके सबक सिखाया था। लेकिन कांग्रेस ने इससे कोई सीख नहीं ली। आज फिर से वह मनमानी कर रही है और देश को लूटने में लगी है। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को यूपीए सरकार की गलत आर्थिक नीतियों से बढ़ रही महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध में 'संपूर्ण क्रांति' की तरह जनांदोलन खड़ा करना होगा। और यह अच्छी बात है कि दिल्ली स्थित रामलीला मैदान में आयोजित 'भ्रष्टाचार विरोधी महासंग्राम रैली' से इसका शंखनाद हो गया है। पूरे देश में इस नारे को गुंजाना होगा कि 'भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाओ–जेपीसी से जांच कराओ।' इस महासंग्राम को तब तक चलाना होगा जब तक भ्रष्टाचारियों को सजा नहीं मिल जाती है। ■

सोनिया गांधी महाअधिवेशन में जन-मुद्दों का जवाब देना क्यों भूल गईं?

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी द्वारा 19 दिसम्बर को जारी प्रेस वक्तव्य

कांग्रेस पार्टी ने अपने अस्तित्व के बाद 125 वर्ष पूरे होने पर 19 दिसम्बर को अपना 83वां पूर्ण अधिवेशन बुलाया। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने बड़े आक्रमणात्मक रूख में बोलने का प्रयास किया ताकि उनके पार्टीजनों को जो बुरी तरह से मनोबल खो गया है, उसमें जोश भरा जाए।

श्रीमती सोनिया गांधी ने अपने भाषण में एक सत्ताधारी पार्टी के नेता के रूप में शासन की सम्पूर्ण विफलताओं की एकदम उपेक्षा की। उन्होंने देश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया क्योंकि उन्होंने उन सवालों का जवाब तक नहीं दिया जिन्हें विपक्ष ने संसद बजट ओर शीतकालीन सत्रों में कांग्रेस से पूछा था। क्या वह भूल गईं कि वह केन्द्र में सत्ताधारी पार्टी की अध्यक्षा हैं? उन्होंने ऐसे सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा कि किस प्रकार से यूपीए–II शासन के दौरान भ्रष्टाचार के अनेकानेक घोटाले सामने आए। भाजपा ने जेपीसी जांच की मांग की और सरकार से संसद की जवाबदेही के लिए कहा जिसे श्रीमती सोनिया गांधी ने 'राजनीतिक ब्लैकमेल' कहकर टाल दिया। स्पष्ट है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने आपात्कालीन स्थिति लगाई थी, वही विपक्ष ही एक सही मांग के लिए भी इस तरह की भाषा का उपयोग कर सकती है।

इस समय कांग्रेस एक ऐसी पार्टी की मानसिकता से ग्रस्त है जो हर तरफ से घिरी हुई है। लगता है कि श्रीमती सोनिया गांधी का भाषण चारों तरफ से घिरी हुई पार्टी की प्रतिक्रिया है। देश के सामने खड़े मूल मुद्दों पर लोगों के सवालों का जवाब देने की बजाए कि वह बोफार्स घोटाले के प्रहार से दबी हुई कांग्रेस आचरण की पुनरावृत्ति मात्र कर रही थीं।

कांग्रेस पार्टी निरंतर ही लोगों से जुदा होती चली जा रही है और इसलिए वह मात्र इतनी रूचि रखती है कि किसी भी तरह से अपनी विफलताओं से लोगों का ध्यान बंटा दे।

यूपीए–II की विफलताओं और बढ़ते जा रहे भ्रष्टाचारों के आरोपों का जवाब देने की बजाए श्रीमती सोनिया गांधी ने लोगों का ध्यान बंटाने का ही रास्ता चुना है। भाजपा सबको बताना चाहती है कि आज राष्ट्र के सामने जो मुद्दे है, वह यह हैं– भ्रष्टाचार, यूपीए–II की सरकार का बेहद विफल प्रदर्शन, लोगों से सरकार की अलहदगी, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के बीच अविश्वास की भावना। कांग्रेस पार्टी को अपने मंथनशील अधिवेशन में अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि एक बार फिर से अवसर मिलने पर भी आज चुनौती के रूप में खड़े मूल मुद्दों पर लोगों को जवाब देना कैसे भूल गई है?

अटल जी की दीर्घायु हेतु सर्वधर्म प्रार्थना सप्ताह का शुभारम्भ

भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 86वीं वर्षगांठ पर उनकी दीर्घायु की कामना लेकर भाजपा नई दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने 21 दिसम्बर को पार्टी केन्द्रीय कार्यालय में भावभीनी धर्म संध्या का आयोजन किया। इसमें पार्टी के वरिष्ठजनों तथा सैंकड़ों कार्यकर्ताओं ने उपस्थित रहकर पूर्व प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी की दीर्घायु की प्रार्थना ईश्वर से की। कार्यक्रम दो घंटे से अधिक समय तक चला। श्रोताओं को भाई अजय जी की मधुर वाणी में सर्वधर्म प्रार्थना और आध्यात्मिक कथा वाचन का लाभ प्राप्त हुआ। यह कार्यक्रम 25 दिसम्बर को वाजपेयी जी के 86वें जन्मदिन पर कालकाजी मंदिर में आयोजित कथा संध्या के साथ समाप्त होगा। इसके पूर्व 21 दिसम्बर से 25 दिसम्बर तक क्रमशः हनुमान मंदिर, कनॉट प्लेस, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, सांई मंदिर लोधी रोड, पहाड़ी गुरूद्वारा ग्रेटर कैलाश–। पर कथावाचन के कार्यक्रम होंगे।

केन्द्रीय कार्यालय में आयोजित प्रार्थना तथा कथा संध्या में सांसद एवं प्रभारी भाजपा दिल्ली प्रदेश श्री एम. वेंकैया नायडू, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुख्तार अब्बास नकवी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री विजय गोयल, नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा प्रो. विजय कुमार मलहोत्रा, अध्यक्ष भाजपा दिल्ली प्रदेश श्री विजेन्द्र गुप्ता, पूर्व राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भाजपा श्री संजय जोशी, राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री श्री श्याम जाजू, अध्यक्ष स्थायी समिति दिल्ली नगर निगम श्री योगेन्द्र चांदोलिया, विधायक करण सिंह तंवर, प्रदेश महामंत्री एवं विधायक श्री रमेश बिधूड़ी, प्रदेश महामंत्री श्री प्रवेश वर्मा, नई दिल्ली भाजपा जिला अध्यक्ष श्री पंकज जैन सहित भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। ■

भारत–इस्राइल के बीच सम्पर्क व संवाद बढ़ाने की जरूरत

हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने इस्रायली सरकार के आमंत्रण पर इस्रायल की सद्भावना यात्रा की। यात्रा का उद्देश्य था कृषि, सिंचाई, जल–प्रबंधन, नवीनकरणीय ऊर्जा, फसल उत्पादन, नेनोटेक्नालॉजी और बायोटेक्नालॉजी क्षेत्रों के आपसी हितों जैसे विषयों पर संयुक्त भारत–इस्रायल अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का अध्ययन करना।

इस्राइल के उप प्रधानमंत्री श्री डान मेरीडोर को गणेश प्रतिमा भेंट करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी

श्री गडकरी जी की छह दिन की यात्रा में उनके शिष्टमण्डल में भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल थे जिनमें राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल, राष्ट्रीय महामंत्री तथा पूर्व राजस्थान मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनकड़, के साथ–साथ श्री सतपाल मलिक, श्री सुभाष देशमुख और मानवेन्द्र सिंह (सभी पूर्व–सांसद) और श्री विजय जौली, सह–संयोजक, भाजपा विदेश कार्य प्रकोष्ठ भी शामिल थे।

भाजपा अध्यक्ष की यात्रा का उद्देश्य यह भी था कि हम भारत और इस्रायल के बीच जन से जन सम्पर्क को बढ़ावा दें। इस्रायली विदेश मंत्रालय की ओर से 2009 के अन्तर्राष्ट्रीय सर्वे में यह कहा गया है कि विश्व में भारत ही सर्वाधिक इस्रायल–समर्थक देशों में आता है।

इस्रायल की संसद में शिष्टमण्डल का भव्य स्वागत

16 दिसम्बर को इस्रायली 'क्नेसेट' (संसद) के स्पीकर ने भाजपा अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी और उनके शिष्टमण्डल का विशिष्ट आगन्तुक दीर्घा में तथा ट्रजरी और विपक्ष के सदस्यों ने ताली बजाकर एवं डेस्क थपथपा कर भव्य स्वागत किया।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी का स्वागत करती हुईं भारत–इस्राइल मित्र–संघ की अध्यक्षा सुश्री अनत बर्नस्टेन रिच

बाद में इस्रायली उप प्रधानमंत्री श्री डान मेरीडोर ने बताया कि आज संसद के सत्ताधारी और विपक्षी सदस्यों ने अपनी सारी परम्पराएं और नियम तोड़कर आपका स्वागत मेजे थपथपाकर किया है, वह अपने आप मे अभूतपूर्व है।

अनुसंधान और विकास उद्यमों का दौरा

16 दिसम्बर को ही श्री गडकरी और शिष्टमण्डल ने कृषि–तकनीकी उद्योगों, सिंचाई और जल प्रबंधन क्षेत्रों के आपसी हितों से जुड़े अनुसंधान और विकास संयुक्त उद्यमों का दौरा करते हुए बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक और उत्तराखण्ड जैसे क्षेत्रों में विस्तार करने पर अपनी सहमति जताई।

इस्रायली उप–प्रधानमंत्री ने श्री गडकरी को आश्वस्त किया कि इस्रायली सरकार को कार्ययोजना 2008–2010 के कार्यक्षेत्र को भारत के राज्यों मे भी विस्तार करने में प्रसन्नता होगी। इस कार्य योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को 'सिनाडको' के विशेषज्ञों की मदद से विस्तार किया जाता है।

श्री गडकरी ने कहा कि मैं एनडीए शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों को कार्य

योजना में शामिल होने के लिए लिखूंगा और दोनों देशों के क्रमिक संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए कहूंगा।

इस्रायल ने दो मिलियन यूएस डालर से पूसा में डेमोन्स्ट्रेशन फार्म परियोजना को पूरा किया है। प्राइवेट सेक्टर ने भी इस्रायली टेक्नालाजियों और संयुक्त उद्यमों की स्थापना में ड्रिप सिंचाई प्रणाली एवं फ्लोरिकल्चर और हार्टिकल्चर को तैयार करने में अपनी रूचि दिखाई है। दोनों देशों के बीच सहकारिता गतिविधियों सम्बंधी एजेण्डा की अन्तः सरकारी कार्ययोजना पर 10 मई 2006 को हस्ताक्षर हो चुके हैं।

श्री गडकरी का राजनैतिक स्तर पर जन सम्पर्क को बढ़ावा देने का आह्वान

17 दिसम्बर को तेल अवीव में इस बात पर जोर दिया कि भारत और इस्रायल को अपने देशों के बीच जन से जन सम्पर्क के विषय में राजनैतिक स्तर पर संवाद करने उनके बीच सम्पर्क बढ़ाने की जरूरत है ताकि आपसी हितों में मामले में एक दूसरे के साथ बंधन और मजबूत हो सकें। यह बात इस्रायल की सत्ताधारी एवं विपक्ष की पार्टियों के साथ हुई मुलाकातों के बीच उभर कर सामने आई।

श्री गडकरी और उनके शिष्टमण्डल ने इस्रायली 'क्नेसेट' (संसद) की विपक्ष की नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुश्री ट्जीपीलिवनी और पार्लियामेंट्री इण्डिया–इस्रायल ग्रुप के अध्यक्ष सुश्री रेशेल अदात्तो, दोनों ही मुख्य विपक्षी कदीमा पार्टी से जुड़ी है, सत्ताधारी लिकुड पार्टी और उप–प्रधानमंत्री श्री डान मेरीडोर के साथ मुलाकात की।

श्री गडकरी का कार्यक्रम बहुत ही व्यस्त था और उन्होंने अनेक अनुसंधान विकास के संयुक्त उद्यमों को देखा जिनमें मछली–पालन, खाद्य–प्रसंस्करण, डेयरी–उद्योग और कृषि–तकनीक उद्योगों से सम्बंध था। उन्होंने इन क्षेत्रों के विशेषज्ञों से परामर्श करते हुए इस्रायल के उत्तम बीजों की तक्नालॉजी की जानकारी ली जो फसल उत्पादन में बेहतर उपज में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

भारत और इस्रायल को अपने देशों के बीच जन से जन सम्पर्क के विषय में राजनैतिक स्तर पर संवाद करने उनके बीच सम्पर्क बढ़ाने की जरूरत है ताकि आपसी हितों में मामले में एक दूसरे के साथ बंधन और मजबूत हो सकें।

एक स्वागत समारोह में बोलते हुए श्री गडकरी इस्रायली उद्यमियों से कहा कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवाओं, फार्मास्युटिकल्य और कृषि–तकनीकी उद्योगों में निवेश के अच्छे अवसर है। उन्होंने कहा कि ''हम एनडीए शासित राज्यों में इन क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। ''भारत–इस्रायली सम्बंधों के प्रमुख प्रोमोटर रीना पुष्करना द्वारा आयोजित इस भोज में इस्रायल के उद्यमी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री नेतान्याहू द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध भारत का समर्थन

18 दिसम्बर को जेरूसलम में इस्रायल के प्रधानमंत्री श्री बेंजमिन नेतान्याहू ने फिर पुष्ट किया कि इस्रायल हर प्रकार से आतंकवाद के साथ लड़ने में भारत के साथ सहयोग करने के प्रति वचनबद्ध है।

उन्होंने भाजपा अध्यक्ष श्री गडकरी को बताया कि इस्रायल भारत की सुरक्षा के प्रति चिंता में शामिल है और इस सम्बंध में नई दिल्ली के साथ सहयोग कर रहा है।

इस्रायली प्रधानमंत्री ने श्री गडकरी से फोन पर बात की और उन्हें इस्रायली सरकार के आमंत्रण पर इस्रायल यात्रा करने के लिए धन्यवाद दिया।

श्री गडकरी ने इस्रायली सरकार द्वारा उनका और उनके शिष्टमण्डल के हार्दिक स्वागत के लिए आभार प्रगट किया और कहा कि भाजपा इस्रायल के साथ मित्र सम्बंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा ने श्री नेतायाहू को बताया कि हमने अनुसंधान और विकास की गृह–सुरक्षा, कृषि–तकनीक उद्योगों, मछलीपालन, सिंचाई, जलप्रबंधन आदि जैसे अनेक क्षेत्रों को देखा है और उन्हें बताया कि हम दोनों देशों के इन संस्थानों के क्षेत्रों में, विशेष रूप से राजग शासित राज्यों में, अनुसंधान और प्रशिक्षण में भागीदारी बढ़ाना चाहेंगे।

श्री गडकरी इस्रायली सेंट्रल बैंक के गवर्नर स्टाले फिशर से भी मिले और दोनों देशों के नवीन क्षेत्रों में व्यापार की संभावनाएं तलाशेंगे।

वर्ष 2009 में हीरो का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 41.9 प्रतिशत रहा। 2009 में भारत से इस्रायल को निर्यात की अन्य प्रमुख वस्तुओं में डायमण्ड, प्लांट्स और सब्जी उत्पादन, वस्त्र और परिधान, बेस मैटल और मशीनें रहीं।

इस्रायल से भारत को निर्यात की गई प्रमुख वस्तुओं में खनिज पदार्थ, डायमण्ड, बेस मेटल, मशीनें, ट्रांसपोर्ट उपस्कर और टेलीकॉम तथा साफ्टवेयर प्रोडक्ट एवं सेवाएं शामिल थीं।

भारत सरकार की औद्योगिक नीति और प्रोमोशन विभाग उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2000 से अप्रैल 2010 तक इस्रायल से भारत को एफडीआई का प्रवाह 51.87 मिलियन यूएस डालर बैठता है। बहुत सी इस्रायली कम्पनियों में अमेरिका और यूरोप के देशों के माध्यम से भी निवेश किया है। ■

जयराम रमेश ने भारतीय हितों के साथ समझौता किया : अरुण जेटली

Hkkरत द्वारा "Domestically supported adaptation and mitigation" के रिपोर्टिंग, विश्लेषण और सत्यापन के सम्बंध में भारत द्वारा उठाए गए कदमों पर पर्यावरण मंत्री श्री जयराम रमेश ने भारत की स्थिति बदल दी है। 3 दिसम्बर 2010 को भाजपा ने इस विषय पर विस्तारपूर्वक अपनी टिप्पणी दी थी।

हाल में कानकुन में मंत्री महोदय ने अन्तर्राष्ट्रीय रूप से वैध बाध्यकारी उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों की स्वीकार्यता के सम्बंध में भारत की स्थिति को बदल दिया है। भारत की पारम्परिक स्थिति यह थी कि जो देश प्रदूषण फैलाते हैं उन्हें ही पर्यावरण का भुगतान करना पड़ेगा और उपचार भी करना होगा। किन्तु, भारत एक जिम्मेदार देश के रूप में स्वैच्छिक रूप से कटौती कर सकता है परन्तु वे देश अन्तर्राष्ट्रीय रूप से वैध बाध्यकारी उत्सर्जन की कमी के लक्ष्यों के आधार पर ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब यह मामला वर्ष 2009 में उठाया गया था तो 29.09.2009 को मंत्री महोदय ने मुझे और कुछ अन्य सांसदों को स्पष्ट रूप से लिखा था–

''भारत कभी भी अन्तर्राष्ट्रीय रूप से वैध–बाध्यकारी उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि यूएनएफसीसी विकासशील देशों को किसी उत्सर्जन कमी की आवश्यकता नहीं है। यूएनएफसीसी के अनुसार जीएचजी उत्सर्जन को कम करने की प्रमुख जिम्मेदारी विकसित देशों की है क्योंकि उनका ही पहले भी और अब भी विश्व में उत्सर्जन में सबसे बड़ा हिस्सा होता है। हमारा राष्ट्रीय जीएचजी उत्सर्जन अब भी बहुत कम होता है,

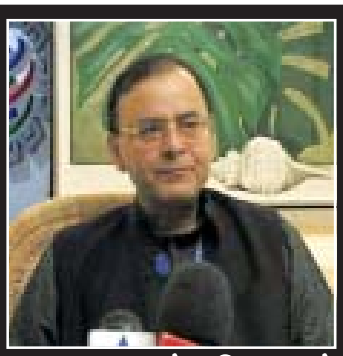

राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली द्वारा 10 दिसम्बर 2010 को जारी प्रेस वक्तव्य

विशेष रूप से जब हम इसे प्रति व्यक्ति के आधार पर देखते हैं और स्पष्ट है कि जैसे–जैसे विकास होता जाएगा तो स्वाभाविक है कि इसमें भी वृद्धि होगी। निर्धनता उन्मूलन और सामजिक एवं आर्थिक विकास हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है।''

तदोपरांत 7.12.2009 को जब मैंने और मेरे कुछ सहयोगियों ने इस विषय को राज्य सभा में उठाया तो मंत्री ने साफ तौर पर कहा–

''पहली बात जिस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है, वह यह है कि हम किसी भी हालत में वैध रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कमी में कटौती को स्वीकार नहीं करेंगे। 8 दिसम्बर 2010 को मंत्री महोदय ने कानकुन में भाषण दिया, जिसका मुद्रित पाठ इंटरनेट पर देखा जा सकता है। इसे तैयार पाठ में भारत की औपचारिक स्थिति दी गई है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी कटौती की स्वीकार्यता का कोई उल्लेख नहीं है। किन्तु भाषण पढ़ते हुए मंत्री महोदय ने पाठ से हट कर कहा–

''सभी देशों को समुचित विधि–सम्मत रूप में बाध्यकारी प्रतिबद्धता की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।''

मंत्री जी का दावा है कि वह केबिनेट के आदेश के अन्तर्गत काम कर रहे थे। अब वह शब्दों से खिलवाड़ कर रहे हैं और पीटीआई के उद्धरण में उनका कहना है– ''मैंने तो इतना मात्र कहा था कि सभी देशों को समुचित विधि–सम्मत रूप में बाध्यकारी प्रतिबद्धता की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत इस समय वैध रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धता की जिम्मेदारी ले रहा है; हमारी यही स्थिति है।''

यह खण्डन स्पष्ट है समझ में आने वाला नहीं है। या तो मंत्री महसूस करते हैं कि वह बहुत बड़े होशियार है या फिर देश को उनका बदलता चेहरा नहीं दिखता है। मंत्री ने जो दृष्टिकोण अपनाया है, वह संसदीय निर्देशों के खिलाफ है। पिछले अनेक वर्षों से चली आ रही भारत की स्थिति के एकदम विपरीत है। उनके लचीले रूख ने भारत के हितों के साथ समझौता किया है। वर्षों की कठोर मेहनत के बाद जो बात तैयार की गई थी, उसे उन्होंने तोड़ दिया है। चीन के प्रतिनिधि अब भी स्वैच्छिक अनुकूलता और हलका करने तक सीमित है और वे वैध रूप से बाध्यकारी कटौती के लिए तैयार नहीं है। भारत सरकार को बताना चाहिए कि लचीले रूख की आड़ में इस विषय पर यह 'रेंगने' की प्रक्रिया क्यों अपनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कानकुन में भारत सरकार की ओर से दिए गए मंत्री जी की बदलती स्थिति की गहरी निंदा करती है। यह दृष्टिकोण किसी भी तरह से भारत की महत्वकांक्षा को नहीं दर्शाता है। ■

जनता की अदालत में भ्रष्टाचारियों का करेंगे पर्दाफाश : राजग

राजग नेताओं द्वारा संयुक्त प्रेस कांफ्रेस में 14 दिसम्बर, 2010 को जारी वक्तव्य

दिवल हठधर्मिता के कारण संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने लोगों को गुमराह करने के लिए एक अभियान चलाया है ताकि वे यह सोचने लगे कि विपक्षी दल पूरे सत्र की विफलता के लिये उत्तरदायी है। राजग पहले से ही लोगों के समक्ष तथ्य रख चुका है और यह बात सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार, घोटालों में लिप्त तथा कमजोर संप्रग सरकार ने संसद को, राष्ट्र के इतिहास में करदाताओं के पैसे की भारी लूट में शामिल दोषी पुरूषों एवं महिलाओं को बचाने के लिए, झुकने पर विवश कर दिया है।

भारत के लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार कांग्रेस की नस–नस में व्याप्त है। गत अनेक दशकों में एक के बाद दूसरी कांग्रेस सरकार ने न केवल सरकारी धन को खुले तौर पर लूटा बल्कि संस्थानों को कमजोर किया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का दमन किया और अपना हित साधने वाली अन्य प्रकार की प्रक्रियाओं को अपनाया जिनसे राष्ट्र का नैतिक ढांचा मूल रूप से नष्ट हुआ। कांग्रेस ने हर हालत में सत्ता में बने रहने के लिये हताश होकर धन–बल और बाहुबल के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया को बेहद व्यवस्थित रूप से भ्रष्ट बनाया। आपातकाल इस प्रवृति का एक ज्वलन्त उदाहरण है।

यद्यपि वर्तमान भ्रष्टाचार के स्तर को देखते हुए बोफोर्स घोटाले की धनराशि बहुत ही कम है, तथापि बोफोर्स घोटाला आज भी प्रत्येक भारतीय को खटकता है। संप्रग सरकार ने तो इटली के Wheeler-dealer ओटावियो क्वात्रोची के लंदन बैंक के खाते, जिसमें बोफोर्स सौदे में ली गई रिश्वत का पैसा जमा किया गया बताया जाता है, को पुनः खुलवाने का कार्य कर डाला। बोफोर्स रिश्वत कांड से बरी होने के बाद हौसला बुलंद होने के बाद की

राजग के राष्ट्रीय संयोजक श्री शरद यादव के नई दिल्ली आवास पर आयोजित संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस को सम्बोधित करते गठबंधन के कार्यकारी अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी।

कांग्रेस सरकारें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने में जुट गईं और प्रणाली को इस हद तक तोड़–फोड़ दिया, जिससे सुनिश्चित हो सके कि दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही न हो सके। यूरिया घोटाले को, जिसमें टर्की के संदिग्ध व्यापारियों को सरकारी धन की अदायगी की गई, जबकि कोई भी उर्वरक भारत नहीं पहुंचा, अभी भी लोग भूले नहीं है।

ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जब स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि सरकार द्वारा खर्च किये जाने वाले एक रूपये में से केवल 15 पैसे गरीबों तक पहुंचते हैं, तब वह वास्तव में गत कई दशकों से उनकी पार्टी द्वारा देश में किये गये भ्रष्टाचार की बात स्वीकार कर रहे थे। परन्तु स्पष्टतया एक ईमानदार प्रधानमंत्री के संरक्षण में संप्रग सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व कांग्रेस सरकारों को भी मात दे दी है।

यद्यपि राजग ने बड़े पैमाने पर हुए 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति की मांग की थी, तथापि तथ्य यह है कि गैर–राजग दलों, जिनमें वामपंथी तथा अन्य क्षेत्रीय दल शामिल हैं, ने हमारी मांग का समर्थन किया, जिससे कांग्रेस का संसद के अन्दर तथा संसद के बाहर

अलग–थलग होना प्रमाणित होता है। वास्तव में, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, संप्रग के अनेक सहयोगी दलों ने भी जेपीसी के लिये विपक्षी दलों की जायज मांग को स्वीकार करने के लिये मनाने का प्रयास किया। परन्तु कांग्रेस ने हठधर्मिता दिखाते हुए इसके औचित्य को मानने से इन्कार कर दिया और संसद के पूरे सत्र को जेपीसी का गठन न किये जाने के लिए एक भी विश्वसनीय कारण बताये बिना बलि चढ़ाने की बात को तरजीह दी।

राजग चाहती थी कि संसद चले क्योंकि वह राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाला, भारतीय जीवन बीमा निगम और सरकारी क्षेत्र के बैंकों जैसी सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा संदिग्ध कम्पनियों को भारी धनराशि दिया जाना, MNREGA में धनराशि की भारी हेरा–फेरी जैसे अन्य बड़े घोटालों पर चर्चा करना चाहती थी। घोटालों के अलावा, राजग जम्मू और काश्मीर में विद्यमान स्थिति जैसे राष्ट्रीय चिंता के अन्य मुद्दों को भी उठाना चाहती थी। वह तथाकथित सरकारी वार्ताकारों द्वारा की गई बेतुकी टिप्पणियों के बारे में भी सरकार से स्पष्टीकरण चाहती थी, जिनकी भूमिका की परिभाषा अभी तक स्पष्ट नहीं की गई है। राजग भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के प्रति केन्द्र सरकार की सतत उदासीनता का मामला भी उठाना चाहती थी और उस "फिक्सर" के बारे में भी विस्तृत जानकारी की मांग करना चाहती थी, जिसने पीड़ितों के लिए एक आधा–अधूरा सौदा किया, जैसाकि कानूनविद् बी. सेन की आत्मकथा में बताया गया है।

हम सरकार से यह भी कहना चाहते थे कि वह देश को बताये कि उसने मुद्रास्फीति रोकने और आम आदमी को राहत देने के लिए तुरंत कदम उठाने हेतु सर्वसम्मत से पारित संकल्प को लागू करने के लिए क्या किया है। सरकार ने मानसून सत्र में पारित संकल्प की भावना की न केवल उपेक्षा की जबकि आम आदमी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हो रही भारी वृद्धि के नीचे पिस रहा है। अतः यह कहना कि राजग की दोनों सदनों की कार्यवाही चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, सच्चाई के पूर्णतया विपरीत है और कांग्रेस यह बात भलीभांति जानती है।

सरकार के पास छिपाने के लिए सभी कुछ था और राजग के पास संसद के माध्यम से राष्ट्र के समक्ष इन घोटालों की सच्चाई पेश करके अपने लिए फायदा उठाने के लिए सभी कुछ था। राजग नेताओं ने न केवल सरकार द्वारा जेपीसी की मांग को स्वीकार करने के तुरंत बाद दोनों सदनों की सामान्य कार्यवाही शुरू करने में सरकार को पूरा समर्थन देने का वायदा किया बल्कि देर तक बैठाकर बर्बाद हुए समय की भरपाई करने की भी पेशकश की थी। यदि सरकार इस प्रकार की हठधर्मिता न दिखाती तो सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर पूर्ण चर्चा की जा सकती थी और विधायी कार्य एक अच्छे वातावरण में पूरा किया जा सकता था।

कांग्रेस जेपीसी के लिये राजी क्यों नहीं हुई? देश के लोगों को यह जानने का अधिकार है और कांग्रेस को इसका उत्तर देना होगा। परन्तु हम जानते हैं कि संप्रग को चिंताए हैं। पहली, वह नहीं चाहती थी कि सांसदों द्वारा भ्रष्टाचार के मुद्दे की बारीकी से जांच हो क्योंकि यह मुद्दा उस अवधि से भी ज्यादा अवधि तक जीवित रहता जितना सत्तारूढ़ दल चाहता है।

दूसरी, यह बात और भी अधिक स्पष्ट हो गई थी कि स्पेक्ट्रम घोटाले से एकमात्र बदनाम पूर्व मंत्री ए. राजा को ही लाभ नहीं हुआ है। इस घोटाले से ऐसे अन्य व्यक्तियों को भी फायदा हुआ है, जिन्हें कांग्रेस पार्टी बचाना चाहती थी।

यदि सरकार का यह मानना है कि मामला अब दब जायेगा, तो हम उन्हें पूरे विश्वास के साथ बता सकते हैं कि वह ख्याली पुलाव पका रही है। राजग के दृष्टिकोण को उच्चतम न्यायालय द्वारा समय–समय पर की गई घोषणाओं तथा टिप्पणियों से समर्थन मिला है। इस मामले की सतर्कता आयोग द्वारा छानबीन न कराये जाने के सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के लिए भी उच्चतम न्यायालय ने सरकार को लताड़ा है। उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा विरोध दर्ज कराने के बावजूद पी. जे. थॉमस को मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किये जाने पर भी आपत्ति की है। चिकने–घड़े की तरह इस सरकार ने सरकारी धन की शर्मनाक लूट और बाद में इस मामले को दबाने के बारे में हुई जोरदार आलोचना को नजर–अंदाज करना उचित समझा।

अब जबकि सरकार ने संसद की सामान्य कार्यवाही नहीं होने दी, ताकि इसके अपने लोगों का और पर्दाफाश न हो, राजग ने ये मुद्दे सीधे लोगों के समक्ष रखने का निर्णय किया है। हम शीतकालीन सत्र को बर्बाद करने की सफलता पर सरकार को खुशी मनाने और आत्मतुष्टि नहीं करने देंगे। 22 दिसम्बर, 2010 से राजग भारत के इतिहास में सबसे अधिक भ्रष्ट सरकार का पर्दाफाश करने के लिए देशभर में एक निरंतर अभियान चलायेगी। हम घोटालों में लिप्त संप्रग सरकार के विरूद्ध जनमत जुटाने के लिए देश के कोने–कोने में जायेंगे।

राजग तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक सरकारी खजाने से गबन किये गये एक–एक रूपये के लिए सरकार को उत्तरदायी नहीं ठहरा लेता। हम भ्रष्ट लोगों का पर्दाफाश करने के इस महायज्ञ में प्रत्येक राष्ट्रभक्त भारतीय का समर्थन और उसकी पूर्ण भागीदारिता की मांग करते हैं और गत 6 वर्षों में देश को लूटने वाले लोगों के विरूद्ध उचित कार्यवाही किये जाने की मांग करते है। अब यह मामला जनता की

2जी स्पेक्ट्रम घोटाले ने देश के भावी चुनावों की दिशा तय कर दी है : अरुण जेटली

& loknnkrk }kjk

2जी स्पेक्ट्रम और भ्रष्टाचार' विषय पर 10 दिसम्बर 2010 को नई दिल्ली में आयोजित एक विचार गोष्ठी में बोलते हुये नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा श्री अरूण जेटली ने कहा कि देश एक विचित्र राजनीतिक परिस्थिति से जूझ रहा है। भ्रष्टाचार और घोटालों पर प्रधानमंत्री मौन हैं परन्तु देश जवाब चाहता है। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो प्रकृति रास्ता बताती है। बिहार विधानसभा के चुनाव ने देश की भावी दिशा तय कर दी है। आने वाले चुनाव 'गुणवान लोगों का शासन या माँ–बेटे का शासन' मुद्दे पर लड़ा जायेगा।

उन्होंने कहा कि भारत अब वंशवाद और अच्छे लोगों द्वारा शासित लोकतंत्र में से किसी एक शासन को चुनेगा। देश में यूपीए का शासन समाप्त होने को है। तीसरा मोर्चा अपनी उपयोगिता पश्चिम बंगाल और केरल विधानसभा चुनावों के बाद समाप्त हो जायेगा। आने वाले दिन राजग गठबंधन सरकार के दिन होंगे। वर्तमान सत्ता के सूत्रधारों ने बड़ी चतुराई से 'मौन प्रधानमंत्री' को विदेश दौरे पर भेज दिया है। श्री मनमोहन सिंह भविष्य में भाषण देने वाले और भ्रमण करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में जाने जायेंगे।

1.76 लाख करोड़ रूपए के 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले का विस्तृत विवरण देते हुए श्री जेटली ने सभागार में उपस्थित अधिवक्ताओं के बीच कहा कि इस बहुचर्चित घोटाले की पटकथा पहले लिख ली गई थी। इसीलिए यह भारत के एक सुनियोजित घोटाले के रूप में इतिहास में दर्ज होगा। श्री जेटली ने ललकारने के अंदाज में सत्तापक्ष को खुली चुनौती दी कि वह जहां से चाहे वहां से 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच करा ले शर्त यही है कि जांच संयुक्त संसदीय समिति ही करेगी। उन्होंने सवाल किया कि आखिर यूपीए सरकार जेपीसी जांच से इतना घबराती क्यों है? शीतकालीन सत्र के मूल्यवान दिन संसद के बहिष्कार में चले गये परंतु सरकार इसी बात पर अड़ी रही कि कोई और जांच करा लो लेकिन जेपीसी जांच की बात न करो। हम भी इसी बात पर कायम हैं कि जांच होगी तो जेपीसी ही करेगी अन्यथा विपक्ष सड़कों, गलियों, चौराहों पर उतर कर यूपीए सरकार के चेहरे से सारा नकाब उतार कर ही दम लेगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पिछले तीन साल से देश के इस सबसे बड़े घोटाले पर सबकुछ जानते हुये भी परदा डाले हुये थे। अब उनकी भी कलई खुल चुकी है। यदि जेपीसी जांच होती है तो आने वाला इतिहास वर्तमान तथाकथित ईमानदार प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार को चुप रहकर सहने वाले प्रधानमंत्री के रूप में जानेगा। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की सारी कहानी दूध और पानी की कहानी की तरह है। दूसरी बार बड़े समझौते कर यूपीए सरकार सत्ता में आई और उसको इसकी भरपूर कीमत भी देश बेचने तक की कीमत चुकाकर चुकानी पड़ी।

भाजपा दिल्ली प्रदेश विधि प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित '2जी स्पेक्ट्रम और भ्रष्टाचार' विषयक संगोष्ठी को संबोधित करते राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली

टेलीकॉम के इतिहास में ऐसा कहीं कभी भी नहीं हुआ कि 2.00 बजे बोली खोली जाये और 2.15 बजे बोली बंद कर दी जाये। बोली लगाने वाले विदेशी खिलाड़ियों को यह भी न बताया जाये कि बोली में कितनी कीमत की जमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट जमा करना है। जिनसे सौदा पहले से ही पट गया था उन 9 भारतीय खिलाड़ियों के जमानत

राशि के बैंक ड्राफ्ट दो दिन पहले ही बनकर तैयार हो गये थे। कितना अजीब लोकतंत्र बन गया है भारत यूपीए के शासनकाल में कि गठबंधन में शामिल एक दल बताता है कि उसे कौन सा विभाग चाहिए और इस विभाग का मुखिया उस दल का कौन व्यक्ति होगा। बेचारा प्रधानमंत्री चुपचाप उस दल के घोटालेबाज व्यक्ति को चुपचाप संचार मंत्रालय सौंप देता है। पहले दिन से ही मंत्री घपले करना शुरू कर देता है। प्रधानमंत्री सबकुछ देखता सुनता है लेकिन मौन रहता है। यदि जेपीसी जांच हुई तो घोटाले की परतें प्याज की परतों की तरह अलग–अलग हो जायेंगी। सारा देश, विश्व भारत के इस घोटाले की तह में बैठे लोगों को जान जायेगा, इसीलिए सरकार भाग रही है जेपीसी जांच कराने से।

गोष्ठी में अपने विचार व्यक्त करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में वर्ष 2010 गंभीर घोटालों के वर्ष के रूप में जाना जायेगा। इस वर्ष 1.76 लाख करोड़ रूपए का 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, 1000 करोड़ रूपए का आदर्श सोसायटी घोटाला, 1000 करोड़ रूपए का सार्वजनिक वितरण प्रणाली घोटाला, 70 हजार करोड़ रूपए का राष्ट्रमंडल खेल घोटाला आदि बड़े घोटाले हुये हैं। छोटे घोटाले तो यूपीए के शासनकाल में लगभग हर रोज होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश के दस बड़े घोटालों में घोटालेबाज जनता का तीन लाख करोड़ रूपया पहले ही हजम कर चुके हैं। पहले हुये प्रमुख घोटाले इस प्रकार हैं : बोफोर्स घोटाला–800 करोड़ रूपए, हवाला कांड–900 करोड़ रूपए, हर्षद मेहता शेयर बाजार घोटाला–4000 करोड़ रूपए, केतन पारिख मेडिकल कॉलेज घोटाला–1000 करोड़ रूपए, तेलगी स्टाम्प घोटाला–20,000 करोड़ रूपये, सत्यम घोटाला–14,000 करोड़ रूपए आदि। ये घोटाले यूपीए सरकार का सच बताने के लिए काफी हैं। आश्चर्य तो इस बात का है कि यूपीए अध्यक्षा अपने सांसद चुनाव के समय चुनाव अधिकारी के सामने पर्चा भरते हुये यह शपथपत्र दाखिल करती हैं कि उनके पास कार तक नहीं है। उन्होंने कहा कि अब देश को घोटालेबाजों से सिर्फ राजग शासन ही बचा सकता है।

गोष्ठी का आयोजन भाजपा दिल्ली प्रदेश विधि प्रकोष्ठ ने किया था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों में कार्य देख रहे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया। सभागार खचाखच भरा था। लोग सभागार के बाहर माइक पर श्री जेटली का सारगर्भित भाषण सुन रहे थे। धन्यवाद ज्ञापन किया अजय दिग्पाल ने। संगोष्ठी में सर्वश्री भूपेन्द्र यादव, वाणी त्रिपाठी, आरती मेहरा, डॉ. हर्ष वर्धन, राजन खोसला, निर्मला सीतारमण, एच एस फुल्का, राजेन्द्र आर्य, श्रीकान्त शर्मा, पवन शर्मा, आशीष सूद, प्रवेश वर्मा, रजनी अब्बी, अभय वर्मा, राजन तिवारी, संजय कौल, डॉ. सम्भित पात्रा, विवेक शर्मा, अनिल गोयल, महेन्द्र गुप्ता, राजीव बब्बर आदि वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे। ■

'भ्रष्टाचार विरोधी महासंग्राम' के लिए प्रभारियों की घोषणा

22 दिसम्बर से शुरू हो रहे कांग्रेस नेतृत्व वाली यू0पी0ए0 सरकार के खिलाफ '' भ्रष्टाचार विरोधी महासंग्राम'' की तैयारी के लिए भाजपा ने विभिन्न राज्यों में प्रभारियों को तैनात किया है।

एन0डी0ए0 द्वारा दिसम्बर को दिल्ली के रामलीला मैदान से शुरू हो रहे ''भ्रष्टाचार विरोधी महासंग्राम'' में एन0डी0ए0 के सभी प्रमुख नेता भाग लेंगे। भ्रष्टाचार के विरूद्ध, इस राष्ट्रव्यापी आन्दोलन को धारदार एवं प्रभावी बनाने के लिए भाजपा ने सभी आन्दोलन वाले राज्यों के लिए पार्टी के प्रमुख नेताओं को प्रभारी नियुक्त किया है।

वरिष्ठ नेता एवं उपाध्यक्ष श्री मुख्तार अब्बास नकवी दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद में होने वाले आन्दोलन, रैली की जिम्मेदारी संभालेंगे महामंत्री श्री विजय गोयल, कोलकता एवं गोवाहाटी, महामंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान पटना, भुवनेश्वर, महामंत्री श्री जे0पी0 नड्डा लुधियाना, अहमदाबाद, श्री किरीट सोमय्या जयपुर, मुम्बई तथा श्री भूपेन्द्र यादव चेन्नई में होने वाले आन्दोलनों व रैली की कमान संभालेंगे। पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज एन0डी0ए0 घटक दलों के साथ आन्दोलन का समन्वय करेंगी। जबकि भाजपा की ओर से सभी कार्यक्रमों का समन्वय महामंत्री श्री अनन्त कुमार करेंगे। लगभग दो माह तक चलने वाले इस ''भ्रष्टाचार विरोधी महासंग्राम'' के तहत दिल्ली, मुम्बई, लखनऊ, हैदराबाद, कोलकत्ता, गोवाहाटी, पटना, भुवनेश्वर, लुधियाना, अहमदाबाद, जयपुर, रोहतक एवं चेन्नई में एन0डी0ए0 की रैलियां होंगी। इसके साथ ही विभिन्न प्रदेशों में जिला, तहसील एवं गांव के स्तर तक भ्रष्टाचार विरोधी महासंग्राम के माध्यम से कांग्रेस नेतृत्व वाली यू0पी0ए0 सरकार के भ्रष्टाचार, घोटालों का काला चिट्ठा जन–जन तक पहुंचाने का अभियान चलाया जायेगा। राज्यों में होने वाले अलग–अलग कार्यक्रमों में भाजपा–एन0डी0ए0 के वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। ■

पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि जनविरोधी कदम : प्रकाश जावडेकर

पेट्रोल के मूल्य में छठी बार की गई वृद्धि पूर्णतया अनुचित और जन–विरोधी है। 22 दिसम्बर से पेट्रोल के मूल्य में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप मुद्रास्फीति बढ़ेगी और सामान्य महंगाई पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने 26 जून, 2010 को पेट्रोल के मूल्यों में 3.88 रूपये की वृद्धि की थी। उस समय सरकार ने पेट्रोल मूल्य तंत्र को नियंत्रण–मुक्त किया था। तब से लेकर आज तक सरकार ने 6 महीने के अंदर पेट्रोल मूल्यों में 8.41 रूपये की वृद्धि की है।

सरकार इस वृद्धि का कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों में हुई वृद्धि बता रही है। जोकि पूर्णतया अनुचित है। पहले, सरकार ने उस समय मूल्यों में वृद्धि की जब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का मूल्य बढ़कर 140 डॉलर प्रति बैरल हो गया था। अब, यह 100 डॉलर प्रति बैरल है। सरकार ने केवल 1रूपया प्रति लीटर मूल्य कम किया जबकि मूल्य गिरकर 80 डॉलर प्रति बैरल हो गया था। परन्तु मूल्य में 8 रूपए की वृद्धि की गई है जबकि मूल्य 100 डॉलर प्रति बैरल है।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद श्री प्रकाश जावडेकर द्वारा बुधवार, 15 दिसम्बर, 2010 को जारी प्रेस वक्तव्य

दूसरी बात यह है कि भारत में आयातित पेट्रोल मूल्य लगभग 26 रूपये है परन्तु सरकार उस पर 30 रूपये प्रति लीटर की दर से ड्यूटी लगाती है। यह विश्व में कर की सबसे ऊँची दर है। तीसरी बात, कम वसूली का तर्क नाममात्र है, क्योंकि सभी तेल कम्पनियां लाभ कमा रही हैं। चौथी बात, अर्थव्यवस्था के इस स्तर पर पेट्रोल और डीज़ल ऐशो आराम की चीज नहीं हैं। बल्कि एक आवश्यकता है।

भाजपा की मांग है कि इस मूल्य–वृद्धि को तुरंत वापस लिया जाए।

यह वृद्धि इस प्रकल्पना के आधार पर की गई कि मुद्रास्फीति कम हो गई है, परन्तु जहां तक बाजार में खाद्य मूल्यों का संबंध है, यह बात सही नहीं है। सरकार ने अगस्त, 2010 से थोक मूल्य सूचकांक गणना का समूचा आधार ही बदल दिया है। इसने इसका आधार वर्ष 93–94 से बदल कर 2004 कर दिया है। इससे इसमें 435 मदों को बढ़ाकर 676 मदें कर दिया है। इन परिवर्तनों के कारण खाद्य वस्तुओं का प्रभावीपन 15.4 प्रतिशत कम होकर 14.3 प्रतिशत हो गया है। और इससे अधिक आश्चर्य की बात यह है कि खाद्यान्न (चावल, गेहूं, ज्वार और बाजरा) का नये मूल्यों में अंश केवल 0.4 प्रतिशत ही है। वास्तव में लोगों की थोक मूल्य सूचकांक में घोषित मूल्यों की तुलना में बाजार में अधिक मूल्य देने पड़ रहे हैं।

157 देश उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मुद्रास्फीति के सही सूचकांक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। भाजपा की यह मांग है कि सरकार तुरंत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अपनाये।■

समाजवादी नेता सुरेन्द्र मोहन नहीं रहे

गत 17 दिसम्बर को वरिष्ठ समाजवादी नेता सुरेन्द्र मोहन का आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। स्वर्गीय सुरेन्द्र मोहन भारतीय राजनीति में समाजवाद के प्रमुख स्तंभ थे। वे गांधीवादी चिंतक, विचारक और लोकप्रिय समाजसेवी थे। उनके आकस्मिक निधन से भारतीय राजनीति ने एक प्रखर समाजवादी नेता खो दिया है जिसकी क्षति अपूरणीय है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं मुख्य प्रवक्ता, सांसद श्री रवि शंकर प्रसाद ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि श्री सुरेन्द्र मोहन ने समाजवादी आंदोलन को एक नई दिशा दी। उनके निधन से राष्ट्र ने एक महान समाज सेवी खो दिया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ■

राजग की प्रधानमंत्री से मांग

जेपीसी गठित करें या पद छोड़ें

l;tho dqekj flUgk dh fo'ks"k fjiksVZ

jk ष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मांग की कि वह भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए अगर जेपीसी का गठन करने में असमर्थ हैं तो नैतिक आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दें।

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर संसद में संघर्ष के बाद एनडीए अब सड़कों पर उतर आई है। गत 22 दिसम्बर, 2010 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा नई दिल्ली स्थित रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के विरूद्ध आयोजित महासंग्राम रैली को गठबंधन के घटक दलों–भारतीय जनता पार्टी, जनता दल(यूनाइटेड), शिवसेना और अकाली दल के वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। रैली में हजारों लोगों की संख्या में महिलाओं और युवाओं की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। बेलगाम महंगाई और भ्रष्टाचार से परेशान लोगों के चेहरे पर आक्रोश झलक रहा था और उन्होंने कांग्रेसनीत यूपीए सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। लोग 'बेइमानों को सजा दिलाओ–जेपीसी से जांच कराओ, घोटालों की है सरकार– नहीं चलेगी यह सरकार' जैसे नारे से सभास्थल गुंजा रहे थे।

कार्यक्रम के प्रारंभ में सुप्रसिद्ध राष्ट्रवादी कवि श्री गजेन्द्र सोलंकी ने भ्रष्टाचार के विरोध में कविता–पाठ किया। भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकारी अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी सहित मंचासीन सभी अतिथियों का तलवार भेंटकर अभिनंदन किया।

रैली को संबोधित करते हुए jktx d dk;Zdkjh vè;{k o Hkktik lkalnh; ny d vè;{k Jh ykyÑ".k vkMok.kh ने कहा, 'सन् 1950 को संविधान वर्ष के रूप में जाना जाता है, 1975 को आपातकाल वर्ष के रूप में, इसी तरह से 2010 घोटालों का वर्ष के रूप में जाना जाएगा।' उन्होंने कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर प्रधानमंत्री को जेपीसी जांच की मांग मान लेनी चाहिए क्योंकि यदि किसी के पास जेपीसी जांच स्वीकार करने का अधिकार है, तो वह प्रधानमंत्री ही हैं। मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि वह पद की शक्ति महसूस करें।

श्री आडवाणी ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने अधिकारों का प्रयोग कर घोटाले की जांच के लिए जेपीसी का गठन करना चाहिए। उनमें यह साहस होना चाहिए कि वे जेपीसी के सामने जवाब देने के लिए हाजिर हो सकें। उन्होंने कहा, 'हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री इस बात के लिए इंतजार करते हैं कि 10 जनपथ क्या कहता है।'

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने

तत्कालीन संचार मंत्री ए.राजा द्वारा भेजे गए एक पत्र को केवल स्वीकार करके एक बड़ी गलती की है। उस पत्र में राजा ने 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन से सम्बंधित अपनी योजना का संकेत दिया था।

श्री आडवाणी ने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के एक मंत्री ने संसद में जारी गतिरोध के दौरान उनसे कहा था कि प्रधानमंत्री को जेपीसी से कोई आपत्ति नहीं है और इसके लिए मंत्रियों की एक बैठक बुलाई जाएगी। श्री आडवाणी ने कहा, 'हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बारे में कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैं नहीं बता सकता।'

श्री आडवाणी ने कहा कि राजग की रैली और सड़क पर इसके मौजूदा

संप्रग शासन में घोटा

- 2 जी स्पैक्ट्रम घोटाला
- आदर्श सोसाइटी घोटाला
- चावल निर्यात घोटाला
- सीवीसी नियुक्ति घोटाला
- सत्यम घोटाला

आंदोलन का उद्देश्य जेपीसी जांच के लिए दबाव बनाना है। विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट है।

Hkktik d jk"Vh; vè;{k Jh fufru xMdjh ने कहा कि केन्द्र की सरकार देश को लूटने वाली सरकार है। इस सरकार के दूल्हा हैं ए. राजा और बाराती हैं कांग्रेस में बैठे दलाल। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की मांग को नहीं मानकर देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने 2जी घोटाले की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराने की एक बार फिर मांग की।

श्री गडकरी ने कहा कि मुझसे एक पत्रकार ने पूछा कि कांग्रेस अधिवेशन में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए संकल्प किया गया, इस पर क्या कहेंगे। तो मैंने कहा यह संकल्प कुछ नहीं, 'चोर मचाए शोर' है। आज जो भी घोटाले हो रहे हैं वह कांग्रेस शासित राज्यों में हो रहे हैं। महाराष्ट्र में आदर्श आवास सोसाइटी, जो शहीदों के नाम पर बना था, उसमें 70 प्रतिशत आवास कांग्रेस नेताओं ने अपने रिश्तेदारों को दिया। श्री गडकरी ने कहा कि कांग्रेस पहले अपने घर में भ्रष्टाचार खत्म करे फिर भ्रष्टाचार पर अंकुश की बात करे।

उन्होंने जनता से 'भ्रष्ट' संप्रग सरकार को हटाने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री एवं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को यह उजागर करना चाहिए कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन, राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी एवं मुम्बई के आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले के लिए कौन–कौन जिम्मेदार हैं। उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में नेताप्रतिपक्ष श्री अरुण जेटली और श्रीमती सुषमा स्वराज को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमने संसद में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर संघर्ष

... में घोटाले पर घोटाले

- राष्ट्रमण्डल खेल घोटाला
- सड़ा–गला खाद्यान्न घोटाला
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली घोटाला
- एलआईसी नियुक्ति घोटाला
- आईपीएल कोच्चि घोटाला

किया, लेकिन वहां जवाब नहीं मिला तब हम अब जनता की अदालत में आए हैं।

ykdlHkk esa foi{k dh urk Jherh lq"kek Lojkt ने कहा कि विपक्ष ने जेपीसी की मांग 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच को सुगम बनाने के लिए की थी, लेकिन कांग्रेस–नीत संप्रग सरकार ने इरादतन इसकी उपेक्षा कर दी, क्योंकि यह उसके छिपे ढांचे को उजागर कर सकती थी। श्रीमती स्वराज ने प्रधानमंत्री से सवाल किया, वे जेपीसी से क्यों डरे हुए हैं? उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री अगर आप जेपीसी के खिलाफ हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास छिपाने के लिए बहुत कुछ है।'

श्रीमती स्वराज ने कहा कि राडिया टेपों ने लोकतंत्र के चारों स्तंभों, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और चौथे स्तंभ के घिनौने चेहरे को उजागर कर दिया है, हम जो सवाल उठा रहे हैं, उसका जवाब न तो सुप्रीम कोर्ट के पास है और न ही पीएसी के पास। उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री ने कहा, जेपीसी नहीं, सोनिया गांधी ने कहा, जेपीसी नहीं और मैं आज पूछना चाहती हूं सोनिया जी, जेपीसी क्यों नहीं, मनमोहन सिंह जेपीसी क्यों नहीं?'

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक दागी आदमी को सीवीसी पद पर बिठाया जबकि मैंने सीवीसी नियुक्ति के लिए बनी समिति की बैठक में इसका विरोध किया। हम नहीं चाहते कि दागी को सीवीसी बनाया जाए। प्रधानमंत्री जवाब दें कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाली संस्था के प्रमुख पद पर दागी व्यक्ति की नियुक्ति में आपकी सहमति है या नहीं? प्रधानमंत्री जी, आपके आंख के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है और आप आंख मूंदे हैं तो आप भी भागीदार हैं। आप तटस्थ हैं इसलिए आप भी अपराधी है।

उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान में आयोजित इस महासंग्राम रैली से भ्रष्टाचार के विरूद्ध शंखनाद हो गया है। देश भर में इस तरह की 12 रैलियां होंगी और हम यूपीए सरकार को झुकाकर रहेंगे। अंत में श्रीमती स्वराज ने एक नारे के साथ अपना भाषण समाप्त किया, 'खत्म करो ये भ्रष्टाचार–चलो चलें जनता के द्वार।'

jkT;lHkk esa foi{k ds urk Jh v:.k tsVyh ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कहा कि यदि वह 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की जांच का सामना करने को तैयार नहीं हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले की

जांच में केवल जेपीसी ही न्याय कर सकती है और वही इसकी तह में जा सकती है कि दूसरी पीढ़ी का स्पेक्ट्रम 2008 में बाजार दरों से नीचे क्यों आवंटित कर दिया गया। श्री जेटली ने कहा, 'ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा हो उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और यह भी कि वह पीएसी के सामने तो पेश हो सकते हैं लेकिन जेपीसी के सामने नहीं जाएंगे।'' उन्होंने प्रधानमंत्री की दागी सीवीसी पीजे थामस की नियुक्ति के लिए भी आलोचना की।

श्री जेटली ने मीडिया की दुर्दशा का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में मंत्रियों का आवंटन का निर्णय कॉर्पोरेट घराने और लॉबिइस्ट मंत्रियों के आवंटन का निर्णय करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष ने संसद में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हंगामा न किया होता तो सरकार अभी भी ए. राजा को संचार मंत्री बनाए रखती।

jktx d jk"Vh; l;ktd Jh 'kjn ;kno ने कहा कि देश के खजाने में लूट मची है। जब तक भ्रष्टाचार का इलाज नहीं हो जाता, यह महासंग्राम जारी रहेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि कि देश की रखवाली की जिम्मेवारी जिस पर हो वह यह कहकर नहीं बच सकता कि मैं निर्दोष हूं। घर में चोरी होती है तो चौकीदार हटा दिया जाता है। जेपीसी की हमारी मांग संवैधानिक है और ऐसा भी नहीं है कि पहली बार जेपीसी से किसी मामले की जांच कराई जानी है। इससे पहले भी चार मौकों पर जेपीसी का गठन हो चुका है। फिर यह सरकार जेपीसी से क्यों भाग रही है।

f'ko lsuk lkalnh; ny d urk Jh vuar xhr ने भी प्रधानमंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा कि उनकी सरकार हिन्दू आतंकवाद के नाम पर पूरे देश में दंगे करवाना चाहती है और खुद इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। अकाली दल के वरिष्ठ नेता रतन सिंह अजनाला ने सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस ने जितना देश को लूटा है उतना तो किसी ने भी नहीं लूटा। उन्होंने कहा कि देश को मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा और अब कांग्रेस लूट रही है। इसलिए आए दिन घोटाले हो रहे हैं। इस महासंग्राम रैली का संचालन दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता एवं धन्यवाद ज्ञापन भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री विजय गोयल ने किया। इस महासंग्राम रैली के दौरान भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वश्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया नायडू एवं राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल, लोकसभा में पार्टी के उपनेता श्री गोपीनाथ मुंडे, राज्यसभा में पार्टी के उपनेता श्री एस.एस. अहलूवालिया, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुख्तार अब्बास नकवी आदि वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। ■

प्रधानमंत्री को जेपीसी जांच की मांग मान लेनी चाहिए क्योंकि यदि किसी के पास जेपीसी जांच स्वीकार करने का अधिकार है, तो वह प्रधानमंत्री ही हैं। मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि वह पद की शक्ति महसूस करें। &ykyÑ".k vkMok.kh

मुझसे एक पत्रकार ने पूछा कि कांग्रेस अधिवेशन में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए संकल्प किया गया, इस पर क्या कहेंगे। तो मैंने कहा यह संकल्प कुछ नहीं, 'चोर मचाए शोर' है। &fufru xMdjh

देश की रखवाली की जिम्मेवारी जिस पर हो वह यह कहकर नहीं बच सकता कि मैं निर्दोष हूं। घर में चोरी होती है तो चौकीदार हटा दिया जाता है। जब तक भ्रष्टाचार का इलाज नहीं हो जाता, यह महासंग्राम जारी रहेगा। &'kjn ;kno

प्रधानमंत्री जी, आपके आंख के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है और आप आंख मूंदे हैं तो आप भी भागीदार हैं। आप तटस्थ हैं इसलिए आप भी अपराधी है। &lq"kek Lojkt

यदि प्रधानमंत्री स्पेक्ट्रम घोटाले में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की जांच का सामना करने को तैयार नहीं हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। &v#.k tsVyh

जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों के साथ भेदभाव समाप्त हो

गत 23 दिसम्बर को जम्मू में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक बैठक में जम्मू और कश्मीर की वर्तमान स्थिति पर एक प्रस्ताव पारित किया गया, जो हम यहां अपने सुधि पाठकों के लिए प्रकाशित कर रहे हैं।

लोतंत्रता के बाद 63 वर्ष गुजरने पर भी आज तक की सत्ता में आई सभी कांग्रेस सरकारों ने अपनी ऐतिहासिक भूलों और चिरस्थायी गलतियों के दोहराते रहने से जम्मू और कश्मीर की समस्याएं निरंतर उसी प्रकार बनी हुई हैं। सीमापार से प्रेरित और अलगाववादियों के समय–समय पर बढ़ती हिंसा के कारण आम आदमी के लिए कठिनाईयों और दुखों का दौर पैदा कर दिया है। आज देश के सामने यह भारी चुनौती है कि किस प्रकार से हम राज्य में बार–बार बन रहे गतिरोध का समाधान निकाल पाएं।

जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और है। भारत के साथ इसका विलय सम्पूर्ण और अटूट है। परन्तु राज्य के बारे में भारत के सामने दो गम्भीर चुनौतियां हैं। पहली, विभाजन के कारण आज भी पाकिस्तान कश्मीर को एक अपूर्ण एजेण्डा की तरह निहारता रहता है। दूसरी, स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस सरकारें अपनी नीतियों के कारण पैदा होने वाली समस्याओं को देखने में ऐतिहासिक दूरदृष्टि ही नहीं रख रही हैं, विशेष रूप से भारत करे जम्मू और कश्मीर मामले में नेहरू के दृष्टिकोण से उभरी भारी गलतियों की कीमत चुकानी पड़ रही है।

पं. जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी तत्कालीन सरकार ने तीन चिरस्थायी त्रुटियां की थी। एक, जब पाकिस्तान से लाखों की तादाद में शरणार्थी भारत आ रहे थे तब एक सुझाव दिया गया था कि इनमें से कुछ शरणार्थियों को जम्मू और कश्मीर राज्य सहित देश के विभिन्न भागों में बसाया जाए। ऐसा नहीं होने दिया गया। दो, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने गलती से भारत में राज्य के आरोहण के बारे में लोगों की राय जानने की मांग का समर्थन कर दिया। इसके कारण जनमतसंग्रह की मांग जोर पकड़ गई और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने यह मुद्दा अन्तर्राष्ट्रीयकरण का रूप ले गया। तीन, इस चाल के दीर्घकालीन निहितार्थों को पहचाने बिना हमारी प्रथम सरकार ने जम्मू और काश्मीर के लिए अलग संविधान बनाने की सहमति दे दी और साथ ही यह भी कहा कि यह अलग स्थिति केवल अस्थायी और कुछ समय के लिए रहेगी।

पिछले 63 वर्षों में पं. नेहरू की सरकार की इस अदूरदर्शिता की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इसके विपरीत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता के अपने तीन वर्ष के जीवन काल में भारत की सभी रियासतों को मिला कर वर्तमान भौगोलिकीय स्थिति में खड़ा कर दिया। सरदार पटेल द्वारा रियासतों को मिलाने से आज भारत के सामने कोई चुनौती खड़ी नहीं रही है। पं. नेहरू ने केवल एक ही राज्य जम्मू और कश्मीर का जिम्मा संभाला था। वहीं उनकी गलतियों की हमें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है।

बार–बार मुद्दे का अन्तर्राष्ट्रीयकरण, सीमापार आतंकवाद की प्रेरणा से 'आजादी' की व्यर्थ सी उम्मीद, अलगाववादियों द्वारा हिंसा के जारी रखने के प्रयास और घाटी में आतंक इन सभी कारणों से जम्मू और काश्मीर में अलग स्थिति का सिद्धांत कायम हो रहा है। अलग स्थिति बनाए रखने का 63 वर्ष का सफर राज्य को पूरी तरह से विलय करने में आड़े आ रहा और अलगाववाद की तरफ बढ़ रहा है।

आज स्वायत्तता, स्व–शासन और आजादी के विभिन्न समर्थक हैं; ये सभी भारत और राज्य के बीच संवैधानिक तथा राजनैतिक सम्बंधों को कमजोर करना चाहते हैं। एक कमजोर और दृष्टिहीन केन्द्र सरकार इनके निहितार्थों को समझने तक में असमर्थ हैं।

जब तक कांग्रेस और केन्द्र की यूपीए सरकार यह नहीं समझती है कि यह समस्या गलत दृष्टिकोण रखने से पैदा हुई है और जब तक वैकल्पिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाएगा तब तक जम्मू और कश्मीर समस्या का कोई हल निकल नहीं पाएगा। हमारे सामने एक चुनाव करने की बात है कि हम जम्मू और काश्मीर राज्य तथा केन्द्र के बीच राजनैतिक और संवैधानिक

सम्बंध मजबूत करें या इसे और अधिक कमजोर बनाएं। अलगाववादी इस सम्बंध को पूरी तरह से मिटा डालना चाहते हैं। क्या हमें उनके जाल में फंस जाना चाहिए। एएफएसपीए को समाप्त करने की मांग अलगाववादियों के उद्देश्य को अपना हाथ ऊपर रखने में मददगार ही साबित होगा और सुरक्षा बलों का मनोबल गिरगा।

जम्मू और काश्मीर राज्य को अलग स्थिति में रखने का परिणाम यही होगा कि केन्द्र सरकार के पास केवल इतना संवैधानिक अधिकार रह जाए कि उसके पास भारत की प्रतिरक्षा, भारत की रक्षा, करेंसी, विदेशी मामले तथा टेलीकम्युनिकेशन रह जाए। शेष सभी अधिकार राज्य सरकार के पास चले जाएंगे। भारत के संविधान में समवर्ती शक्तियां मूलतः जम्मू और कश्मीर के पास हैं। अवशेष शक्तियां जो केन्द्र में निहित अन्य राज्यों के सम्बंध में हैं, वह जम्मू और काश्मीर राज्य के पास है। संवैधानिक परिवर्तन के रूप में जो 1953 में हुए थे, उनमें सुप्रीम कोर्ट और भारत के निर्वाचन आयोग के न्यायाधिकारों को जम्मू और काश्मीर पर लागू किया गया। बाद में, आतंकवाद से निपटने के लिए केन्द्र को अधिकार सौंपे गए। आज, केन्द्र और राज्यों के बीच सम्बंध, जिनमें पर्याप्त शक्तियां जम्मू और काश्मीर के पास ही निहित है। अब किसी भी वर्तमान शक्तियों को जम्मू और काश्मीर को स्थानांतरित करने की जरा भी गुंजाइश नहीं है। यदि जरूरत है तो इतनी ही है कि अन्ततः अन्य राज्यों के पास जो अधिकार हैं, वैसे ही अधिकार जम्मू और काश्मीर को देकर सभी राज्यों को बराबरी पर खड़ा किया जाए। क्या राज्य की सुरक्षा, भारत की प्रतिरक्षा, करेंसी, विदेशी मामले और टेलीकम्युनिकेंशस सम्बंधी किसी भी अधिकार को स्थानांतरित करने की बात सोची भी जा सकती है? क्या ऐसी कोई ऐसी संभावना हो भी सकती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट या भारत के निर्वाचन आयोग के अधिकारों को कम करके उन्हें जम्मू और काश्मीर को सौंप दिया जाए? क्या राज्यों और केन्द्र के बीच संवैधानिक सम्बंधों को कमजोर किया जा सकता है और राज्य में प्रधानमंत्री या सदर–ए–रियासत जैसे संस्थान बनाए जा सकते है?क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कोई इस प्रकार का प्रयोग करे तो यह राज्य के लिए विनाश को ही आमंत्रित करेगा।

भारत सरकार को भारतीय संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित उस प्रस्ताव के दायरे में दृढ़ता से काम करना चाहिए कि पाक–अधिकृत कश्मीर भारत का अंतरंग भाग है। राज्य के लोग बहुत दुख उठा चुके हैं। अब समय है कि राज्य के निवासियों को सुख, शांति और सुरक्षा मिले।

आज काश्मीर घाटी की स्थिति पर शांत भाव से विश्लेषण करने की आवश्यकता है। अनुच्छेद 370 ने राज्य के लोगों के खिलाफ ही काम किया है। इससे राज्य और शेष भारत के बीच मनोवैज्ञानिक बाधा ही खड़ी की है। यह राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करने में आड़े आई है। लोगों के राज्य में आने–जाने की रूकावट के कारण राज्य का भारत के साथ स्वाभाविक विलय नहीं हो पाया है। इसने अलगाववादियों के साथ स्वाभाविक विलय नहीं हो पाया है। इसने अलगाववादियों को ही आशा बंधाई है जो कश्मीर के अंदर हों या बाहर, वह यह समझते हैं कि राज्य और भारत के राजनैतिक और संवैधानिक सम्बंधों को तोड़ा जा सकता है। हमारा मानना है कि अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया जाए।

पाकिस्तान ने शुरू शुरू में भारत को कश्मीर के जुदा करने की मंशा पूरी कर पारम्परिक युद्ध की चाल चली। इससे स्वतंत्रता के आरम्भ के कुछ वर्षों में सफलता मिली जिससे हमारे क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण भाग हमसे छीन लिया गया। एक ऐसा वातावरण बनाया गया जिससे सभी धार्मिक अल्पसंख्यक जैसे पार्टी के कश्मीरी पंडित और सिख जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक घाटी से निकल गए। यह एक तरह से जातियों के आधार पर सफाई अभियान चलाया गया। किन्तु बाद में महसूस हुआ कि भारत की पारम्परिक संख्या कहीं अधिक है। फिर सीमापार से आतंकवाद के प्रयास किया गया और 'प्राक्सी वार' शुरू की गई। किन्तु पिछले दो दशकों से, भारत में सैन्य और पुलिस बलों की संख्या बढ़ी ताकि आतंकवाद को कुचला जा सके। इसके अलावा भी, दुनिया में आतंकवाद का फल खाने की इच्छा खत्म हुई। तब अलगाववादियों को महसूस हुआ कि यह चाल बेकार हो चुकी है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने जन विरोध का नया तरीका ढूंढा है और यह है पत्थर फेंकना। उनके समर्थकों का दावा है कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है परन्तु कारगर रूप से यह हिंसा का ही एक वैकल्पिक रूप है। अलगाववादियों की रणनीति में हिंसा ही प्रमुख होती है। शांतिपूर्ण काश्मीर में अलगाववादी नेताओं की कोई प्रासंगिक नहीं रह जाएगी। अलगाववादियों की हिंसा प्रतिक्रिया को आमंत्रण देती है। जब पुलिस और सुरक्षा बल हमला करते हैं तो वे अपना

बचाव करते हैं। दोनों तरफ लोग हताहत होते हैं, शांति और सद्भावना बिगड़ती है। इसके परिणामस्वरूप कर्फ्यु या हड़ताल होती है। आम आदमी का जनजीवन बिगड़ता है। उन्हें घबराहट होने लगती है। कश्मीर में कोई इस बात को महसूस नहीं करता है कि आजादी का राजनैतिक स्वरूप क्या होगा? फिर भी कई बार इस घबराहट से विरोध और आक्रोश बढ़ता है। इससे अनावश्यक ही विरोध का स्वरूप बड़ा होता जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि काश्मीर में शांति हो, एक ऐसा काश्मीर बने जिसमें हमारे नागरिक खुशहाल हों और उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद में आर्थिक विकास का सुख मिले। उन्हें हिंसा और आतंक के वातावरण की जरूरत नहीं है। उन्हें जरूरत है कि वे ऐसी सभी बातों से परहेज करें, जो आतंकवादी चाहते हैं।

किन्तु भारत को एक ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो नागरिकों के लिए कल्याणकारी हो और अलगाववादियों के लिए बर्बादी का सबब बने। अलगाववादियों को किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जानी चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार की रियायत नहीं मिले और न ही उनकी संख्या में असाधारण बढ़ोतरी हो अन्यथा उनकी बढ़ती प्रासंगिकता से हिंसा का ही वातावरण तैयार होगा। हमें काश्मीर घाटी में भारत के प्रत्येक नागरिक को विश्वस्त करना होगा कि अलगाववादियों की रणनीति राज्य के नागरिकों में अशांति फैलाना है।

केन्द्र में वर्तमान यूपीए सरकार काश्मीर के बारे में विचार–शून्य हो गई है। घाटी में प्रधानमंत्री की प्रत्येक यात्रा में वह कोई न कोई तदर्थ पहल की घोषणा कर देते हैं। उन्होंने सन् 2006 में पांच कार्यकारी ग्रुप गठित किए। कार्यकारी ग्रुपों से मिले बिना ही चेयरमैन ने एकपक्षीय रिपोर्ट पेश कर दी, जिसमें स्वायत्तता की मांग का समर्थन किया गया। बाद में प्रधानमंत्री की एक और यात्रा में उन्होंने एक ग्रुप के गठन की घोषणा की जो रोजगार पैदा करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बनाने में सहायता करेगा। उन्होंने यह जरा महसूस नहीं किया कि उन्होंने पहले ही अपनी पिछली यात्रा में उसी चेयरमेन की अध्यक्षता में वैसा ही कार्यकारी ग्रुप बनाया था। फिर गृह मंत्री ने 'साइलेंण्ट डायलॉग' की पहल की घोषणा की। स्पष्ट है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक तीन वार्तालापकारों के एक ग्रुप का गठन किया जिन्होंने मीडिया के माध्यम से वार्तालाप शुरू किया, हालांकि घाटी में इसकी प्रतिक्रिया हल्की ही रही। आज काश्मीर ऐतिहासिक मोड पर खड़ा है। काश्मीर के अधिकांश लोग शांति चाहते हैं, वे प्रगति चाहते हैं। यह एक कमजोर सरकार के रहते संभव नहीं है जो भारत की प्रभुसत्ता को कमजोर कर देना चाहती है। इसके अलावा, यह केवल भाजपा का दृष्टिकोण रख कर ही संभव है जो जम्मू और काश्मीर को भारत के साथ पूरी तरह से संवैधानिक रूप से विलय करना चाहती है; भाजपा चाहती है कि लोग सुख–समृद्धि का जीवन व्यतीत करें और जो कुछ अलगाववादी चाहते हैं, उसे पूरी तरह नकार दें।

जम्मू और काश्मीर में विभिन्न क्षेत्र हैं। किन्तु, स्वतंत्रता के बाद से राज्य का प्रशासन प्रमुख रूप से काश्मीर घाटी के प्रतिनिधियों के हाथ में रहा है और जम्मू और लद्दाख के लोगों की मामूली सी ही भागीदारी रही है। इसके कारण जम्मू और लद्दाख दोनों क्षेत्रों में भेदभाव रहने का भाव व्याप्त रहा है। आज शक्तियों के विकेन्द्रीयकरण की जरूरत है और तीनों क्षेत्रों के बीच समान रूप से संसाधनों को बांटा जाना चाहिए। आज यह भेदभाव इन क्षेत्रों में संसदीय तथा विधानसभा की सीटों की संख्या के आवंटन में नजर आता है। सरकारी और अर्ध–सरकारी संगठन में रोजगार और यहां तक कि व्यावसायिक कालेजों सहित सरकारी कालेजों के दाखिलों में यह भेदभाव स्पष्ट दृष्टिगत होता है। संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन सत्ता ही हिस्सेदारी में समानता को रोकने के लिए किया गया है। पश्चिमी पाकिस्तान पाक–अधिकृत क्षेत्र से आने वाले शरणार्थियों को राज्य की स्थिति में स्थान नहीं मिला है। इन सभी बातों के कारण जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों में भेदभाव का भाव पनपता जा रहा है। इन क्षेत्रों में विकास का अभाव भी इस भेदभाव की भावना को बढ़ा ही रहा है। इस प्रकार इन क्षेत्रों में संवैधानिक रूप से सशक्त प्रांतीय परिषदों के गठन की अत्यंत आवश्यकता है।

Lor= Hkkjr e dk'ehj lcl yEc le; ls pyh vk jgh leL;k fujrj cuh gbl gA blds fy, jk"Voknh njnf"V rFkk Hkkjr dh lEiHkrk cuk, j[ku dh n< 'kfDr dh vko';drk gA Hkktik lkQrkj ij dguk pkgrh g fd tEe vkj dk'ehj e py jg HknHkko dk rjr vr gkuk pkfg,A ?kkVh e vkrd vkj fglk d okrkoj.k dk lekIr gkuk pkfg,A

अभियोजन के कारण घाटी छोड़ने को विवश हुए काश्मीरी पंडितों और सिखों के लिए ऐसा वातावरण बने कि वे वापस लौट सकें। अलगाववादियों को विधिसम्मत न बना कर, उन्हें हाशिए पर फेंक दिया जाना चाहिए। भारत सरकार को भारतीय संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित उस प्रस्ताव के दायरे में दृढ़ता से काम करना चाहिए कि पाक–अधिकृत काश्मीर भारत का अंतरंग भाग है। राज्य के लोग बहुत दुख उठा चुके हैं। अब समय है कि राज्य के निवासियों को सुख, शांति और सुरक्षा मिले। ■

कांग्रेस का भ्रष्टाचार से संग्राम का ढोंग

✍ vEck pj.k of'k"B

dkग्रेस इस समय चारों ओर से घिरी पड़ी है। उसकी इतनी पतली हालत कभी न थी। आज वह हर मोर्चे पर विफल खड़ी है। भ्रष्टाचार का अपना ही पाला भूत अब कांग्रेस को ही निगल जाना चाहता है। एक के बाद एक भ्रष्टाचार के घोटालों ने तो उसकी कमर तोड़ कर रख दी है। महंगाई आम आदमी को ही नहीं अमीर को भी काटने लगी है। जिस आदमी का हमदम होने का झांसा देकर उसने चुनाव जीता था उस आदमी की तो अब यह हालत हो गई है कि वह अब यह मानने को तैयार हो गया है कि उसकी तो ज़िन्दगी तब अधिक बेहतर थी जब तक कि कांग्रेस नीत सम्प्रग सरकार न आई थी। अब तो वह इस सरकार को बना कर ही पछता रहा है। प्याज़ की कीमतों ने आम आदमी ही नहीं कांग्रेस के भी आंसू निकाल दिये हैं। बेरोज़गारों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अलगाव व पृथकतावादियों के हौसले बढ़ रहे हैं, विशेषकर काश्मीर में। कांग्रेस स्वयं ही आतंकवादियों की पीठ थपथपा कर उन्हें शह दे रही है। राष्ट्रवादियों को देशद्रोही और आतंकवादियों को अपना बताया जा रहा है। अपने पड़ोसी देशों, विशेषकर चीन व पाकिस्तान से इतने बिगड़े रिश्ते कभी न थे। ये दोनों देश तो वर्तमान सरकार को चीनी–चुपड़ी बातों से अपना ही उल्लू सीधा कर रहें हैं और जहां और जैसे भी होता है भारत को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं गवाते। ऐसी स्थिति में अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस के पास जश्न मनाने के लिये कुछ नहीं है।

कांग्रेस ने महंगाई की चीख और प्याज़ की आसमान छूती कीमतों से निकलते आंसुओं के बीच अपना दो–दिवसीय तो अवश्य सम्पन्न किया पर उपलब्धि के नाम हाथ कुछ न आया। वह केवल यही मीलपत्थर गाड़ सकी कि उसके शासनकाल में उसने एक ऐसा आभास देने का प्रयास किया कि लगे मानो कांग्रेस कुछ कर रही है। कांग्रेस के नेता चालाक तो हो सकते हैं पर जनता की आंखों पर तो पट्टी नहीं बंधी है। वह तो सब कुछ अपनी खुली आंख से देख व महसूस कर सकती है। कांग्रेस यह आभास देने का तो अवश्य प्रयास किया कि स्थिति काबू में है पर साथ ही जनता को भी पता चल गया कि स्थिति काबू कांग्रेस सरकार के नहीं अपितु मुनाफाखोरों, चोर–बाज़ारी करने वालों, भ्रष्टाचारियों, अपराधियों व असामाजिक तत्वों के हाथ है। कांग्रेस ने आक्रामक तेवर ही अपना सुरक्षा कवच बनाने का प्रयास किया।

कांग्रेस हुई चौकन्नी

कांग्रेस के राज्य में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है और प्रति दिन उजागर होते घोटालों का अंबार लग गया जिस में पार्टी ही विलुप्त होने लगी है। कांग्रेस ने स्वतन्त्र भारत के इतिहास में भ्रष्टाचार के घोटालों का रिकार्ड कायम कर दिया जो प्रतिदिन टूटता जा रहा है। सच्चाई तो यह है कि अब तक जो उजागर हुआ है वह तो अंश मात्र है। यही कारण है कि वावजूद इसके कि संसद का सारे का सारे शातकालीन सत्र विपक्ष द्वारा 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के लिये संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग और कांग्रेस की इस मांग को न मानने की ज़िद्द के सिर चढ़ गया। अब तो जनता के मन में यह संशय घर करता जा रहा है कि कांग्रेस संयुक्त संसदीय समिति का गठन केवल इस कारण नहीं करना चाहती है कि भ्रष्टाचार के उसके और गड़े मुर्द उजागर हो उठेंगे।

जब पानी सिर के उपर से निकल गया तो पार्टी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी चौकस हो उठीं। अब उन्हें भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये कुछ करने की सूझी और अपने भाषम में चार–सूत्री कार्यक्रम की घोषणा कर दी। इससे तो स्पष्ट है कि वह अब तक भ्रष्टाचार को ही आश्रय दे रहीं थीं वरन् उन्होंने अब तक कुछ किया क्यों नहीं?

चूहे खाकर बिल्ली हज को चली

अब तक कांग्रेस सरकारें अपने ऐच्छिक अधिकारों के बलबूते पर ही तो भाई–भतीजावाद को बढ़ावा दे रहीं थीं। जब इस पर आलोचना होती तो वह इसका समर्थन करते थे। अब श्रीमती सोनिया गांधी ने अपने मुख्य मन्त्रियों व सरकारों को आदेश दे दिया है कि वह अपने ऐच्छिक अधिकारों को तिलांजलि दे दें। इस आदेश पर वस्तुतः कितना असर होता है यह तो समय ही बतायेगा पर श्रीमती गांधी अभी तक यह नहीं बता पाईं कि अब तक इस व्यवस्था को उन्होंने क्यों चलने दिया?

चलो देर से ही सही पर इतना तो अवश्य लगता है कि कांग्रेस सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली'' वाली कहावत चरितार्थ करने जा रही है।

भ्रष्टाचार और सज़ा

अपने भाषण में श्रीमती गांधी बहुत

आक्रामक थीं। उन्होंने अपने विरोधियों को पूछा कि हमने तो भ्रष्टाचार के आरोप पर अपने मुख्य मन्त्री बदल डाले और मन्त्रियों से त्यागपत्र ले लिये पर उन्होंने क्या किया है? उनके इस तर्क पर हंसी आती है। क्या कांग्रेस के पास भ्रष्टाचार मिटा देने का यही परम दण्ड है? उन्हें यह सज़ा बहुत है जिन्होंने गरीबों के खज़ाने को करोड़ों–अरबों का चूना लगाया। क्या कांग्रेस ने किसी कांग्रेसी मन्त्री–मुख्य मन्त्री को आपराधिक सज़ा दिलवाई है। श्रीमती गांधी समझती हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप में कुछ नेताओं को पद से हटा कर मानों उन्हें तो महान् आदर्श सज़ा ही दे दी हो। जिनके नाम लेकर कांग्रेस अपना दामन साफ होने का दम भरती है उसकी दूसरी तसवीर यह है कि वह सब अभी भी कांग्रेस के सम्मानीय नेता व पदाधिकारी हैं, उदाहरण के लिये सर्वश्री अशोक चव्हाण, सुरेश कलमाड़ी, शशि थरूर व अन्य।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध लडाई का ढोंग

वस्तुतः भ्रष्टाचार की तो जननी ही कांग्रेस है। उसके शासनकाल ही में उसका जन्म व पालनपोषण हुआ। भ्रष्टाचार के विरूद्ध कांग्रेस की लड़ाई हवा में तलवारें चलाने से अधिक कुछ नहीं है। डींगें तो बहुत मारती है पर वस्तुतः देती बढ़ावा व संरक्षण भ्रष्टाचार को ही है।

केन्द्रिय जांच ब्यूरो, जो राजनैतिक हलके में कांग्रेस जांच ब्यूरो के नाम से जाना जाने लगा है, उसका कांग्रेस भ्रष्टाचार निवारण के लिये नहीं, अपने राजनैतिक विरोधियों के विरूद्ध दुरूप्योग कर अपना राजनैतिक उल्लू सीधा कर रही है। क्वात्रोची का मामला ही लो जिसके गांधी परिवार से सम्बन्ध जगज़ाहिर हैं। यह भ्रष्टाचार के विरूद्ध निर्णायक लड़ाई का ही तो सबूत है कि क्वात्रोवी के बैंक खातों पर रोक हटा कर घूंस का सारा धन उसके हवाले कर दिया। उसके विरूद्ध आपराधिक मामला भी वापस ले लिया गया।

क्योंकि तब कांग्रेस को अपनी संप्रग सरकार बनाये रखन के लिये श्री लालू प्रसाद के समर्थन की आवश्यकता थी इसलिये मनमोहन सरकार ने उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा न खटखटाया जब उच्च न्यायालय ने उनके तथा उनकी पत्नि श्रीमती राबड़ी देवी के विरूद्ध ज्ञात श्रोतों से अधिक धन–सम्पत्ति एकत्रित कर लेने के मामले में उन्हें बरी कर दिया।

अदालत ने बिहार के चारा घोटाले के सम्बन्ध में कई मामलों में निर्णय देकर दोषियों को सज़ा भी सुना दी है पर इस घोटाले के प्रमुख अभियुक्त श्री लालू के विरूद्ध मामला अभी भी कई साल से राजनैतिक कारणों से लटका कर रखा गया है।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की मुख्य मन्त्री सुश्री मायावती तथा पूर्व मुख्य मन्त्री श्री मुलायम सिंह के विरूद्ध भी ज्ञात स्रोतों से अधिक धन–सम्पत्ति एकत्रित कर लेने के मामले सीबीआई के पास हैं और उन पर भी वह अपना स्टैण्ड उसी प्रकार बइलती रहती है जैसाकि वह सरकार के प्रति बदलते रहते हैं। उन पर भी जांच लम्बित रखी गई है ताकि समय–समय पर कांग्रेस को समर्थन देने केलिये उनके कान मरोड़े जा सकें। यह है संक्षेप में कांग्रेस की भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ाई का सच्च।

युवराज ने ढूंढा आम आदमी

अन्ततः कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने पिछले छः वर्ष से अधिक के कठिन परिश्रम के बाद आम आदमी को परिभाषित कर ही दिया। अपने भाषण में उन्होंने बताया कि आम आदमी वह है जो व्यवस्था से अभी तक नहीं जुड़ा है। पर उन्होंने यह नहीं बताया कि उस गुनाह के लिये उत्तरदायी कौन है? स्वतन्त्रता के बाद लगभग पचास वर्ष तो केन्द्र व राज्यों में कांग्रस की ही सरकारें रही। आज भी पिछले छ' वर्ष से अधिक समय से सोनिया–राहुल प्रेरित सरकार ही चल रही है।

जिन्नाह भी शर्मिन्दा किये

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस ने भी सत्ता में बने रहने केलिये अंग्रेज़ों के ''फूट डालो और राज करो'' के फार्मूले को जारी रखा। पर अब जब 2010 में कांग्रेस को विभिन्न चुनावों, विशेषकर बिहार विधान सभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी, तो उसने अब देश को बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों में बांटना शुरू कर दिया है। अब उसने अल्पसंख्यक मतदाताओं को भ्रमित करने केलिये ''हिन्दू व भगवा आतंक'' का नया हौवा खड़ा करने की कुचेष्ठा शुरू कर दी है। आज की सोनिया–राहुल कांग्रेस तो मुहम्मद अली जिन्नाह से भी आगे निकल गई है। टाइम्स आफ इण्डिया (दिसम्बर 20) में एक समाचार छपा है जिसका शीर्षक है ''राष्ट्रवाद के नाम पर नाज़ियों की भान्ति भाजपा मुसलमानों का वध कर रही हैः दिगविजय''।

सिखों को न्याय क्यों नहीं?

अपने एक प्रस्ताव में कांग्रेस अधिवेशन ने सरकार से आग्रह किया कि वह सुनिश्चित करे कि 2002 के गुजरात दंगों में दोषियों को सज़ा दिलाई जाये। पर हैरानी की बात है कि कांग्रेस 1984 में कांग्रेस प्रेरित सिख विरोधी दंगों में मरने वालों के लिये कांग्रेस ने एक भी शब्द नहीं बोला जिन की संख्या गुजरात से कहीं अधिक है और जो केवल उन्हीं प्रदेशों में घटित हुये जहां कांग्रेस सत्ता में थी और आरोपी भी कांग्रेसी ही हैं। सिख भी एक अल्पसंख्यक समुदाय है। फिर यह भेदभाव क्यों?

दिग्विजय का झूठ पर झूठ

कांग्रेस महामन्त्री दिगविजय सिंह

तो इतने भ्रमित हो गये हैं कि वह प्रतिदिन कुछ न कुछ अनाप–शनाप बोलते ही जा रहे हैं। उनकी बात पर ध्यान देना ही फिजूल है। पर 26/11 में मारे गये एटीएस प्रमुख स्वर्गीय श्री हेमन्त करकरे के बारे जो बोलते जा रहे है उसकी चर्चा करना आवश्यक है।

वह फरमाते हैं कि श्री करकरे ने अपनी मृत्यू से दो घंटे पूर्व उनसे बात की और उन्होंने उन्हें बताया कि उन्हें हिन्दू आतंकियों से खतरा है। उनका आरोप था कि करकरे की हत्या कसब ने नहीं की जिस अपराध के लिये अदालत ने उसे मौत की सज़ा सुना दी है। पहले तो उन्होंने दावा किया कि वह फोन के रिकार्ड के आधार पर यह साबित भी कर सकते हैं। फिर मुकर गये कि उन्हें फोन का ब्यौरा उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। अपने झूठ को छुपाने के लिये यह अच्छा बहाना है। उनके इस दावे को गृह मन्त्री पी विदम्बरन ने भी खारिज किया है। दिगविजय के कथन को श्री करकरे की पत्नी श्रीमती कविता ने भी झूठा करार दिया है और कहा है कि वह ऐसा कह कर उनके पति की शहादत का अपमान कर रहे हैं। दिगविजय इस प्रकार पाकिस्तान की ही भाषा बोल रहे हैं और अदालत ने जो निर्णय सुनाया है उस पर प्रश्न निन्ह लगा रहे हैं।

एक प्रश्न यह भी उठता है कि स्व0 करकरे ने केवल यह बात दिगविजय से ही क्यों की? दिगविजय न तो केन्द्र में ही और न महाराष्ट्र में मन्त्री थे। न ही वह महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं। श्री करकरे को यदि सचमुच ही कोई सन्देह या खतरा था तो यह बात उन्हें प्रधान मन्त्री, गृह मन्त्री, प्रदेश के मुख्य मन्त्री या गृह मन्त्री से करनी चाहिये थी जो कोई उचित पग उठा सकते थे। यह दावा कर क्या दिग्विजय यह दावा नहीं कर रहे कि वह तो श्री करकरे से उनकी जीवनसंगिनी श्रीमती करकरे से भी ज़्यादा करीब थे क्योंकि इस बारे अपना दिल तो अपनी पत्नी से भी नहीं खोला। बस इस से अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। ■

(लेखक भाजपा साहित्य एवं प्रकाशन प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक हैं)

सुषमा स्वराज ने उठाये चीनी प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय मुद्दे

श्रीमती सुषमा स्वराज ने अरुणाचल प्रदेश में चीनी अतिक्रमण का मुद्दा उठाते हुये कहा कि चीन को इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिये क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है।

yksकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने भारत की यात्रा पर आये चीन के प्रधानमंत्री श्री वेन जियाबाओं के साथ भारत– पाकिस्तान के बारे में चीन की भूमिका जम्मू कश्मीर के लोगों को नत्थी वीजा तथा अरुणाचल प्रदेश में चीनी अतिक्रमण के मुद्दे उठाये और उनसे भारतीय औषधि तथा सॉफ्टवेयर के लिये चीनी बाजारों को खोलने की मांग की।

भाजपा के मुख्य प्रवक्ता श्री रवि शंकर प्रसाद ने नियमित प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि श्रीमती सुषमा स्वराज ने चीनी प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान कहा कि चीन को भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिये। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद से प्रभावित है और पाकिस्तान इसका प्रायोजक है। ऐसे मे चीन द्वारा तटस्थ भूमिका की बात करना कहां तक जायज है। उन्होंने कहा कि इस तरह की स्थिति में तटस्थता का सवाल ही नहीं उठता।

श्रीमती सुषमा स्वराज ने जम्मू कश्मीर के लोगों को नत्थी वीजा जारी करने की चीन की नीति की भी आलोचना करते हुये इस पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में चीनी अतिक्रमण का मुद्दा उठाते हुये कहा कि चीन को इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिये क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है।

उन्होंने चीनी प्रधानमंत्री से कहा कि जब दोनों देशों के बीच व्यापार बढ रहा है और इसके लिये नये उपाय किये जा रहे हैं तो चीन को भारतीय औषधि क्षेत्र और साफ्टवेयर के लिये अपने बाजारों के खोलना चाहिये। चीनी प्रधानमंत्री ने बातचीत के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा का जिक्र करते हुये उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनके स्वस्थ रहने की कामना की। ■

लेख

मध्यप्रदेश लोकसवा अधिनियम 2010 एक अनुकरणीय कदम

✍ fodkl vkuUn

vkज केन्द्र में एक के बाद एक भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं वहीं मध्यप्रदेश सरकार ने लोकसेवा अधिनियम 2010 बनाकर निचले स्तर पर भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही को कम करने का एक सराहनीय और ऐतिहासिक प्रयास किया है। यह प्रशासन को सरल, सहज और उत्तरदायीपूर्ण बनायेगा। इस तरह यह सुशासन या रामराज्य की ओर एक ठोस पहल है।

बहुत से देशों ने अपने नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सिटीजन चार्टर बनाया है ताकि लोकसेवा की गुणवत्ता बढ़े और एक निश्चित समय में किसी भी सेवा को जनता को मुहैय्या कराया जा सके। लेकिन पहली बार सिटीजन चार्टर के विचार को भारत में मध्य प्रदेश सरकार ने अधिनियम में बदला है ताकि इसका सख्ती से पालन हो सके।

साधारणतया देखा जाता है कि सरकारी अधिकारी नागरिकों के किसी भी कार्य को करने में देर करते हैं और बाध्य करते हैं कि जनता उन्हें अवैध पैसा दे। यह भ्रष्टाचार का भी हमारे देश में एक मुख्य कारण है। कभी–कभी देर होने के कारण उस सेवा का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है।

इन सभी चीजों से निपटने के लिए भाजपा शासित मध्यप्रदेश सरकार ने जुलाई 30, 2010 में लोकसभा अधिनियम 2010 विधानसभान में पारित किया। और औपचारिक रूप से इसे कार्यान्वित अक्टूबर 9, 2010 को किया गया। इस

कानून के अनुसार अब लोकसेवकों को एक निश्चित समय सीमा में लोक सेवाओं को मुहैया कराना होगा। अभी तक इसके अन्तर्गत 9 विभागों को शामिल किया गया है। इन विभागों के अन्तर्गत सेवाएं जैसे– जन्म प्रमाणपत्र, जातिप्रमाण पत्र, डोमिसाईल प्रमाणपत्र, पानी कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन, पैंशन, बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि को रखा गया है।

इस कानून के अनुसार यदि सम्बंधित अधिकारी किसी सेवा को तय सीमा में नहीं करता है तो उसे जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना न्यूनतम 250 रूपए प्रतिदिन और अधितम 5000 रूपए होगा। यह पैसा सम्बंधित सेवा लेने वाले नागरिक को क्षतिपूर्ति के रूप में देना होगा।

यदि उचित समय के अंदर नागरिक कार्य नहीं होता है तो वह दो जगहों पर ऊपर के अधिकारियों को अपील कर सकते हैं। यदि अधिकारी अपीलकर्ता की याचिका के अनुसार कार्य सम्बंधित अधिकारी से उस कार्य को नहीं करवा पाता है तो उसे उचित कारण देना होगा। अन्यथा उन्हें भी 500 रूपए प्रतिदिन की दर से और अधिकतम 5000 हजार रूपए अपीलकर्ता को हर्जाने के रूप में देना होगा।

यह कानून भागीदारी लोकतंत्र ;च्तजपबपचंजवतल कमउवबतंबलद्ध को मजबूत तो करेगा ही साथ ही साथ यह जनोन्मुख प्रशासन की ओर एक कदम है। परंपरागत प्रशासन का तरीका, जो हमें उपनिवेशिक विरासत में प्राप्त हुआ था, का प्रस्थान है।

अभी भी हमारी नौकरशाही औपनिवेशिक मानसिकता से ही काम करती है। अपने को मालिक समझती है। जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझती है। यह अधिनियम सही मायने में उस परम्परागत प्रशासन से निजात दिलाने में सक्षम होगा। इस कानून का लक्ष्य कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति का उत्थान (अन्त्योदय) है जो कि पं. दीनदयालजी का सपना था।

अभी तक आम जनता लोकसेवकों की दया पर निर्भर थी लेकिन यह अधिनियम जनता को यह अधिकार देता है कि एक निर्धारित समय के अंदर प्रशासन से बिना किसी झिकझिक और परेशानी का अपना उचित काम करवा सकें। साथ ही साथ यह कानून यह भी दर्शाता है कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जनता की समस्याओं के प्रति कितने संवेदनशील हैं। यह शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार का ऐतिहासिक कदम है इसे दूसरे राज्यों एवं केन्द्र सरकार को भी अनुकरण करना चाहिए। हालांकि बिहार में राजग सरकार इसी तर्ज पर अधिनियम लाने की तैयारी कर रही है। ■

भाजयुमो फहराएगा श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा

loknnkrk }kjk

देश की एकता एवं अखण्डता के लिए 12 जनवरी 2011 को भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर कोलकता से ''राष्ट्रीय एकता यात्रा'' शुरू करेंगे। यात्रा देश के विभिन्न राज्यों से होती हुई 26 जनवरी, 2011 को श्रीनगर पहुंचेगी, जहां मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर लाल चौक में तिरंगा फहराएंगे। इस अवसर पर देश के सभी हिस्सों से पहुंचे युवा शामिल होंगे।

विगत छह महीनों से जम्मू–कश्मीर अशांत है। आज कश्मीर में हालात जितने खराब है, उतने पहले कभी नहीं थे। जम्मू–कश्मीर अलगाववरूपी बारूद के ढ़ेर पर है। अलगाववादी सीमापार से शक्ति प्राप्त कर घाटी को भारत से अलग करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जम्मू–कश्मीर के मुख्यमंत्री द्वारा कश्मीर के भारत के साथ हुये विलय को चुनौती दी जा रही है। अलगाववादी पूरे देश में घूम–घूम कर भारतीय संप्रभुता को चुनौती दे रहे है। केन्द्र सरकार ने तीन वार्ताकारों का दल नियुक्त किया है, उनकी भाषा और ऐजेण्डा अलगाववादियों से अलग दिखाई नहीं देता।

युवा मोर्चा का मानना है कि जम्मू–कश्मीर की वर्तमान परिस्थितियों के लिये केन्द्र की यूपीए सरकार व राज्य की नेशनल कांफ्रेस सरकार जिम्मेदार हैं। अलगाववादियों के खिलाफ ठोस कार्यवाही करनी चाहिये। लेकिन इसकी बजाये सरकार लचर नीति अपना रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है।

युवा मोर्चा देश का राष्ट्रवादी युवा संगठन है। हम मानते है कि कश्मीर की समस्या से हरेक भारतीय जुड़ा है। कश्मीर की समस्या को लेकर विगत चार महीनों में 18 राज्यों में 39 बड़ी सभायें ''भारत प्रथम अभियान'' के अन्तर्गत की गई। जम्मू–कश्मीर के विलय का स्मरण करते हुये 26 अक्टूबर, 2010 को पूरे भारत में जिला स्तर पर संकल्प दिवस मनाया गया।

मुख्य बिन्दु

- यात्रा 11 राज्यों से गुजरते हुए लगभग 3066.54 हजार किलोमीटर की दूरी तय करेगी।
- यात्रा के क्रम में 150 जनजागरण सभाएं आयोजित की जाएंगी।
- जगह–जगह पर देश के शहीदों के परिवार को सम्मानित किया जाएगा।
- 25 जनवरी 2011 को जम्मू में विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा।
- 26 जनवरी 2011 को लालचौक, श्रीनगर पर तिरंगा फहराया जायेगा।
- तिरंगा वाहिनी – प्रत्येक राज्य में जिला एवं मंडल स्तर पर तिरंगा वाहिनी का गठन किया जायेगा।
- संकल्प पखवाड़ा – 25 दिसम्बर से 10 जनवरी तक ''चलो कश्मीर संकल्प'' पखवाड़ा मनाया जायेगा।

'राष्ट्रीय एकता यात्रा' का शुभारंभ

भारतीय जनता युवा मोर्चा 'भारत प्रथम अभियान' के अर्न्तगत कोलकाता (पश्चिम बंगाल) से 'राष्ट्रीय एकता यात्रा' शुभारंभ करेगा, क्योंकि यहां की माटी युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाषचंद्र बोस और डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी की कर्मस्थली रही है।

यह यात्रा डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी की जन्मस्थली से उनके बलिदान स्थली तक युवा दिवस (12 जनवरी 2010) से गणतंत्र दिवस (26 जनवरी 2011) तक निकाली जाएगी। इस दौरान 11 राज्यों में 150 जन–जागरण सभाएं आयोजित की जाएगी। इस क्रम में देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हुए जवानों के परिवारों का सम्मान किया जाएगा।

राष्ट्रध्वज का सम्मान

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने ही देश में राष्ट्रध्वज तिरंगे का अपमान किया जाता है। जम्मू–कश्मीर में ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि अनेक जगहों पर राष्ट्रध्वज तिरंगा नहीं फहराया जा सकता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तय किया है कि राष्ट्रप्रेम की साकार अभिव्यक्ति के लिए श्रीनगर के लाल चौक पर राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराया जायेगा।

इसी क्रम में 25 जनवरी 2010 को जम्मू में विशाल रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें युवा मोर्चा के लाखों कार्यकर्ता भाग लेंगे और 26 जनवरी को श्रीनगर स्थित लालचौक पर राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय भावना को पुष्ट किया जाएगा।

...शेष पृष्ठ 28 पर

कोयला सत्याग्रह अंधेरे पर प्रकाश का संघर्ष है

प्रदेश की सात करोड़ जनता के घरों को आलोकित करने के लिए पार्टी कार्यकर्ता हर सज़ा भुगतने के लिए तत्पर : प्रभात झा

Hkkरतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री प्रभात झा ने कहा कि मध्यप्रदेश की जनता ने केन्द्र में कमलनाथ, कांतिलाल भूरिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अरूण यादव को निर्वाचित कर केन्द्र में प्रदेश का हित साधने के लिए भेजा है, लेकिन कांग्रेस यूपीए सरकार और केन्द्रीय मंत्री मध्यप्रदेश की जनता को दंडित कर रहे है। मध्यप्रदेश से निकलने वाले कोयला का प्रदेश के बाहर निर्यात किया जा रहा है, लेकिन मध्यप्रदेश के ताप बिजली घरों को आवश्यकता के अनुसार निर्धारित मापदण्डों के अनुकूल कोयला नहीं देकर मध्यप्रदेश के साथ भेदभाव, पक्षपात किया जा रहा है। मध्यप्रदेश को अंधेरे में धकेलने और राज्य सरकार की 24 घंटे बिजली प्रदाय करने की प्रतिबद्धता को खंडित करने के लिए कांग्रेस और यूपीए सरकार साजिश के तहत संघीय भावना के विपरीत आचरण कर रही है। प्रभात झा आज शहडोल जिले के धनपुरी क्रमांक 3 कोयला क्षेत्र में कोयला सत्याग्रह में भाग ले रहे बडी संख्या में कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित कर रहे थे। केन्द्र टकराहट की राजनीति छोडे, संघीय व्यवस्था का सम्मान करें। शिवराजसिंह चौहान के साथ इस संघर्ष में सात करोड़ जनता है।

श्री प्रभात झा ने कहा कि मध्यप्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान मध्यप्रदेश के लिए कोयला के आवंटन और पूर्ति को बनाये रखने के लिए अनेकों बार प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, ऊर्जा मंत्री सुशील शिन्दे, कोयला मंत्री प्रकाश जायसवाल से भेंट कर मध्यप्रदेश की कोयला आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आग्रह कर चुके है, लेकिन मध्यप्रदेश की आवश्यकताओं की निरंतर उपेक्षा कर मध्यप्रदेश को अंधकार परोसने की साजिश की जा रही है। श्री प्रभात झा ने कहा कि मध्यप्रदेश की जनता केन्द्र सरकार से भीख नहीं संविधान के तहत राज्य के हकों की मांग कर रही है। जिसे शर्मनाक ढंग से केन्द्र सरकार ठुकराकर प्रदेश की जनता को कठिनाई में धकेल रही है। इसे भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ता कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को देश में जनता ने जनादेश दिया है। कांग्रेस की कृपा पर सत्ता में नहीं आये है। मध्यप्रदेश के विधायकों, 25 राज्यसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य प्रदेश की मांग को लेकर धरना दे चुके है। प्रधानमंत्री से आग्रह कर चुके है, लेकिन मध्यप्रदेश को उसके संवैधानिक हक से वंचित किया जा रहा है। कोयला सत्याग्रह प्रदेश की जनता के हकों की लड़ाई है और इसे हम सफल बनाकर रहेंगे भले ही इसके लिए जो भी कीमत चुकाना पडे।

मध्यप्रदेश के लिये कोयला, बिजली, राष्ट्रीय राज्यमार्ग, निर्माण, संधारण के लिये प्रावधान इंदिरा कुटीर, बीपीएल के लिए खाद्यान्न आवंटन जैसे सभी मामलों में मध्यप्रदेश के साथ भेदभाव किया जा रहा है और कांग्रेस के केन्द्रीय मंत्री प्रदेश के हितों की रक्षा करने के बजाए कांग्रेस के भेदभावपूर्ण षडयंत्र में भागीदार बन रहे है। उन्होंने आगाह किया कि यदि प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप मांगों पर विचार नहीं किया गया तो प्रदेश की जनता केन्द्रीय मंत्रियों को प्रदेश में प्रवेश करने की इजाजत नहीं देगी।

श्री प्रभात झा ने कहा कि मध्यप्रदेश के साथ यदि केन्द्र सरकार सहयोग करती है और समुचित मात्रा में कोयला की पूर्ति सुनिश्चित की जाती है तो आने वाले दिनों में मध्यप्रदेश में चौबीसों घंटे बिजली की पूर्ति होने के साथ ही राज्य सरप्लस स्टेट बनेगा और अन्य

राज्यों को बिजली देने के लिये सक्षम होगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कृषि और उद्योग में संतुलन लाने के लिये प्रगतिशीलता के साथ व्यूह रचना की है। जिसके परिणाम सामने आने लगे है और प्रदेश प्रति व्यक्ति आय जीडीपी के मामले में अग्रणी राज्य बना है। गांवों में किसानों को बिजली देने के लिये फीडर अलग किये गये है। कोयला आंदोलन अनुशासित और शांतिपूर्ण रहेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री और केन्द्र सरकार को सचेत किया कि कांग्रेस की हठधर्मिता और शोशेबाजों का खामियाजा कांग्रेस की बिहार में भुगतना पड़ा है। बिहार के परिणाम से कांग्रेस को सबक लेना चाहिए।

उन्होंने केन्द्र सरकार की विफलताओं की लंबी फेहरिस्त जनता के सामने रखते हुए कहा कि गोदामों में अरबों रू. का खाद्यान्न सड़ा दिया जाता है, लेकिन गरीबों को खाद्यान्न बांटने में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी यूपीए सरकार और कांग्रेस नीति की बात करती है। उन्होंने कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की मुंबई आतंकी घटना में शहीद हुए हेमंत करकरे की शहादत पर की गयी सियासत को निंदनीय और शर्मनाक बताया। श्री प्रभात झा ने कोयला सत्याग्रह में भाग ले रहे कार्यकर्ताओं के उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश को प्रकाश में रखने का संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक की मध्यप्रदेश के संवैधानिक हकों का सम्मान नहीं किया जाता।

मध्यप्रदेश के शहडोल कोयलांचल के धनपुरी क्रमांक 3 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित कोयला सत्याग्रह का नेतृत्व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री प्रभात झा ने किया। कोयला आवंटन में मध्यप्रदेश के साथ किये जा रहे केन्द्र सरकार के भेदभाव और पक्षपातपूर्ण रवैया को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में बेहद आक्रोश था। शहडोल जिले के अलावा अनुपपुर, उमरिया जिलों के विधायक, जिलाध्यक्ष, पार्टी पदाधिकारी और बडी संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेसनीत यूपीए सरकार की संघीय भावना के प्रतिकूल आचरण पर असंतोष व्यक्त कर रहे थे। उनका मानना था कि कोयला सत्याग्रह मध्यप्रदेश की 7 करोड़ जनता की विवशता है। केन्द्र सरकार न तो एनुअल कान्ट्रेक्टेड क्वान्टिटी में कोयला प्रदान कर रही है और न ही पीएफएल के मापदण्डों का ही पालन कर रही है। मध्यप्रदेश में ताप बिजली घरों के नजदीक उत्खनन होने वाला उत्कृष्ट कोटि का कोयला तो अन्य राज्यों को आवंटित किया जा रहा है जबकि मध्यप्रदेश को दूरदराज कोयला खानों से कोयला उठाने के लिये विवश किया जा रहा है, साथ ही कोयला के आयात को विवश किया जा रहा है। इससे ताप विद्युत घर कुपोषित हो रहे है। ताप बिजली का उत्पादन प्रभावित होने से प्रदेश की जनता को बिजली संकट से गुजरना पडता है। कोयला आवंटन का युक्तियुक्तकरण करने की आवश्यकता रेखांकित की गयी। बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कोयला सत्याग्रह में बडे अनुशासित ढंग से भाग लिया।

सभा के उपरांत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रभात झा के नेतृत्व में प्रदेश सह संगठन महामंत्री अरविन्द मेनन, उपाध्यक्ष विनोद गोटिया, मार्तण्डप्रताप त्रिपाठी, बृजेश कुमार गौतम, राकेश शर्मा, सुदामा सिंह, बली सिंह, सुंदर सिंह, दिलीप जायसवाल, वीणा सिंह, ज्ञान सिंह, लल्लू सिंह, दलपत सिंह, नरेन्द्र मरावी, अनिल गुप्ता, गिरीश द्विवेदी, मिथलेश मिश्रा सहित विधायक, प्रदेश पदाधिकारियों दस हजार कार्यकर्ताओं ने कोयला सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तारी दी। ■

पृष्ठ 26 का शेष

bl ;k=k ;k=k dk mnn'; g& समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जम्मू–कश्मीर की समस्या को लेकर जन–जागरण करना और राष्ट्रीय भावना का अलख जगाना।

भारतीय जनता युवा मोर्चा की निम्नलिखित मांगें हैं :

- कश्मीर समस्या को मात्र मजहबी समस्या न माना जाए। सभी राजनैतिक दल इस समस्या को दलीय राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखें।
- सरकार कमजोर रवैया छोड़े और अलगाववादियों को दो टूक शब्दों में बताये कि जो कुछ भी होगा वह संविधान के दायरे में होगा।
- धारा 370 समाप्त होनी चाहिए।
- सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम से किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो।
- भारतीय संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर संकल्प लिया था कि पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लिया जायेगा। संसद के इस संकल्प को पूरा करने हेतु सरकार आवश्यक कदम उठाये।
- कश्मीर के युवाओं और आम लोगों के लिये सुरक्षित, संपन्न और उत्पीड़न मुक्त जीवन को सुनिश्चित किया जाये।
- विस्थापित कश्मीरी पंडितों का सम्मानजनक प्रकार से कश्मीर घाटी में पुनर्वास होना चाहिये।

हम मानते हैं कि सारा कश्मीर भारत का है और समूचा भारत कश्मीरियों का है। कश्मीर का दर्द भारत का दर्द है। हमें इसे महसूस करना होगा। मां भारती देश के नौजवानों को पुकार रही है। प्रत्येक भारतवासी कश्मीर के प्रति अपने राष्ट्रीय दायित्व को स्वीकारे, तभी कश्मीर बचेगा और देश भी। ■

भाजपा किसानों के हित में आन्दोलन करेगी

& l oknnkrk }kjk

Hkk रतीय जनता पार्टी की ओडिशा राज्य ईकाई की दो दिवसीय कार्यसमिति बैठक भुवनेश्वर में 14 और 15 दिसंबर को सम्पन्न हुई। प्रदेश अध्यक्ष जुएल ओराम की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सरकार से पन्द्रह मांगें मांगने का निर्णय लिया गया। इसमें एक प्रस्ताव पारित करके किसानों के हित के लिए सरकार से लड़ने का निर्णय भी लिया गया।

सभा का उद्घाटन पूर्व केन्द्रीय मंत्री तथा राज्य के भाजपा प्रभारी संतोष गंगवार ने किया। उन्होंने अपने भाषण में आश्चर्य जताते हुए कहा कि पता नहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री ने पोस्को जैसे प्राईवेट कंपनी को शिक्षण संस्थान खोलने के लिए जमीन अधिग्रहण करके क्यों दिया जिसे शिक्षा का कोई अनुभव नहीं है।

ओडिशा सरकार ने बहुत से कानूनों पर्यावरण, वनसंरक्षण, जमीन अधिग्रहण नियम, जगन्नाथ मंदिर से सम्बंधित कानूनों का उल्लंघन करके दिया है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से पद छोड़ने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि यदि वे ऐसे नहीं करते हैं तो आमजन तो इसका सही जवाब देगी ही।

श्री ओराम ने कहा कि सरकार को 20,000 रूपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को क्षतिपूर्ति के रूप में देना चाहिए। क्योंकि गरीब किसानों की फसल असमय वर्षा और मौसम की गडबड़ी के कारण काफी क्षति पहुंची है। मैं पूछता हूं कि प्राईवेट कम्पनियों को सरकार कम पैसे में जमीन और अन्य संसाधन मुहैय्या करा सकती है तो गरीब किसानों को क्षतिपूर्ति की उचित राशि देने में क्यों हिचकिचा रही है। वेदांता ग्रुप को अनैतिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए श्री ओराम ने मुख्यमंत्री की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

उन्होंने कहा कि माननीय उच्च्य न्यायालय ने वेदांता के लिए किसानों से अधिग्रहण की गई जमीन को किसानों को लौटाने का निर्देश दिया है। लेकिन ये नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली सरकार अभी तक इस मुद्दे पर चुप बैठी है।

इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने केन्द्र में यूपीए सरकार और राज्य की बीजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां एक ओर कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार 2जी स्पैक्ट्रम, आदर्श हाउसिंग, कॉमनवेल्थ गेम्स आदि जैसे महाघोटालों में लिप्त है वहीं नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली ओड़िशा सरकार अवैध खनन, अवैध रूप से जल, जंगल और जमीन प्राईवेट कम्पनियों को देने में लगी हुई है। भाजपा इनके खिलाफ अपना विरोध केन्द्र और राज्य दोनों जगहों पर जारी रखेगी।

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा उन्होंने जगन्नाथ मंदिर की जमीन को भी गलत तरीके से प्राईवेट कम्पनी को विश्वविद्यालय खोलने के लिए दे दी। उन्होंने कहा कि जब तक अधिग्रहित की हुई जमीन वास्तविक मालिकों को नहीं लौटाई जाती तब तक भाजपा चुप नहीं बैठेगी और अपना विरोध और तेज करेगी।

कार्यकारिणी की बैठक में सारे राज्य, जिला पदाधिकारी तथा कार्यकारिणी सदस्यों ने भाग लिया। ■

तेलंगाना राज्य गठन के लिए भाजपा की पहल

&l ioknnkrk }kjk

Hkk जपा के वरिष्ठ नेता श्री वेंकैया नायडू के नेतृत्व में भाजपा को एक प्रतिनिधिमंडल ने संसद के बजट सत्र में तेलंगाना राज्य निर्माण के लिए विधेयक लाने हेतु प्रधानमंत्री से आग्रह करते हुए ज्ञापन सौंपा।

भाजपा आंध्र प्रदेश इकाई की तेलंगाना समिति के एक पन्द्रह सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने संसद भवन में माननीय प्रधानमंत्री से 8 दिसम्बर को मुलाकात की और संसद के बजट सत्र में तुरंत ही विधेयक पेश करने की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। इस प्रतिनिधिमण्डल के नेतृत्व श्री जी. किशन रेड्डी, विधायक तथा प्रदेशाध्यक्ष ने किया तथा उनके साथ में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद श्री एम. वेंकैया नायडू और भाजपा प्रभारी एवं सांसद श्री पुरुषोत्तम रूपाला भी शामिल थे।

प्रतिनिधिमण्डल ने प्रधानमंत्री पर बल दिया कि निरंतर अनिश्चितता बनी रहने के कारण राज्य तथा दोनों क्षेत्रों के हितों का नुकसान हो रहा है और इस पर शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री को स्मरण कराया कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ही 2004 और 2009 चुनावों में टीआरएस के साथ चुनाव अभियान चलाते हुए अलग राज्य बनाने का वायदा किया था। उन्होंने पिछले वर्ष 9 दिसम्बर को केन्द्रीय गृहमंत्री के बयान की भी याद दिलाई और उनसे अनुरोध किया कि वे इस प्रक्रिया पर शीघ्र कार्रवाई करें। प्रतिनिधिमण्डल ने माननीय प्रधान से यह भी अनुरोध किया वे राज्य के आंदोलन में शामिल छात्रों के विरूद्ध भी मुकदमे वापस ले लें।

प्रधानमंत्री ने वायदा किया कि वह इस सम्बंध में राज्य सरकार से बात करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जस्टिस कृष्णा समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार कारवाई शुरू करेगी और वे इस बात पर प्रतिनिधिमण्डल से सहमत हुए कि देर तक अनिअश्चितता बनाए रखने से आंध्र प्रदेश के हितों का नुकसान होता है जो राज्य तेजी से प्रगति के पथ पर चल रहा है।

श्री एम. वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री पर बल दिया कि आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के कारण धान और अन्य फसलों को बर्बाद कर राज्य के किसानों, विशेष रूप से तटवर्ती क्षेत्र के किसानों की कमरतोड़ दी है। धान की खड़ी लाखों एकड़ फसलों की कटाई होने ही वाली थी कि वे पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं। पिछले डेढ़ वर्षों में 'लैला साइक्लोन' के बाद 'जल' साइक्लोन की पुनरावृत्ति हुई और अब भारी वर्षा ने कहर ढाया है। किसानों को तो पहले ही अपनी उपजों का अलाभकारी मूल्य मिल रहा था और अब तो उन्हें धान खेतों को बाढ़ में बहते देखना पड़ रहा है जिससे वे बर्बादी के कगार तक पहुंच गए हैं। अतः केन्द्र सरकार को उन्हें बर्बादी से बचाने के लिए बड़े स्तर पर हर प्रकार की मदद करना आवश्यक हो गया हैं। बर्बाद फसलों के लिए किसानों को समुचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार से रिपोर्ट मिलने के बाद एक केन्द्रीय दल वहां भेजा जाएगा और उसकी रिपोर्ट मिलने के बाद केन्द्र सरकार राज्य को निश्चित मदद देगी।■

भाजपा प्रकोष्ठ संयोजकों की घोषणा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने 6 दिसम्बर 2010 को निम्नलिखित प्रकोष्ठ संयोजकों एवं सह–संयोजकों की घोषणा की–

1. श्री मांगेराम गर्ग	l;kstd	आजीवन सहयोग निधि
2. श्री पद्मनाभम् आचार्य	lg&l;kstd	आजीवन सहयोग निधि
3. श्री पद्मनाभम् आचार्य	lg&l;kstd	ओवरसीज फ्रेंडस ऑफ बीजेपी
4. श्री अनिल गुप्ता	l;kstd	नेपाल सम्पर्क प्रकोष्ठ
5. श्री त्रिलोकी नाथ राजदान	l;kstd	जम्मू एवं कश्मीर सम्पर्क प्रकोष्ठ
6. डॉ. श्रीकृष्ण मित्तल	lg&l;kstd	गौ एवं विकास प्रकोष्ठ
7. श्री सुरेश श्रीवास्तव	lg&l;kstd	सहयोग प्रकोष्ठ

■